राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण मंगलवार 24 नवंबर 2026 वर्ष-9,अंक-289 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अयोध्या-जनकपुर के बीच सीधी ट्रेन 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' शुरू

मोदी-बालेन ने दिखाई हरी झंडी, यूपी-बिहार के 10 स्टेशनों पर रुकेगी



लखनऊ (एजेंसी)। भगवान राम की नगरी अयोध्या और माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर धाम के बीच पहली ट्रेन आज से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने हरी झंडी दिखाकर सरयू कमला एक्सप्रेस को रवाना किया। यह ट्रेन यूपी और बिहार के 10 स्टेशनों पर रुकेगी। पहले दिन 1158 यात्री इसमें सवार हुए। आम यात्रियों के लिए यह ट्रेन 28 नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक, राजा दशरथ राम बारात लेकर जब मिथिला में जनकपुर पहुंचे थे तब उन्हें 4 दिन लगे थे। अब यही सफर लगभग 19 घंटे में पूरा होगा। अयोध्या कैंट से जनकपुर धाम के बीच रेल मार्ग की कुल दूरी करीब 604 किलोमीटर होगी। ट्रेन करीब 19 घंटे में यह दूरी तय करेगी। ट्रेन उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग-अलग शहरों से गुजरते हुए नेपाल पहुंचेगी। सरयू कमला एक्सप्रेस के शुभारंभ के मौके पर पूरे अयोध्या रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा रही। स्टेशन के कोने-कोने में मौजूद पुलिसकर्मी लोगों की हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। अयोध्या से जनकपुर के लिए ट्रेन कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना होगी।

अल-नीनो से हिमालय में भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा

भारत-नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में बाढ़ का अनुमान

नई दिल्ली (एजेंसी)। अल नीनो मजबूत होने से हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। इससे सर्दियों में भारत और नेपाल में बाढ़ आ सकती है। नेपाल में भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है। हिंदूकुश हिमालय विंटर आउटलुक 2026 के अनुसार, नेपाल के अलावा अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी इसका असर रहेगा। यहां बारिश और ठंड ज्यादा होने का अनुमान है। अमेरिका की नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, अल नीनो मजबूत से बहुत मजबूत स्थिति में है। इसके 1950 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद सबसे मजबूत बनने की संभावना करीब 60 फीसदी है। यह रिपोर्ट काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स ने मिलकर तैयार की है। **ज्यादा बारिश, बर्फबारी, सूखा और जंगलों में आग का खतरा-** वैज्ञानिकों ने कहा कि अल नीनो से हिमालय की तलहटी में ज्यादा बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी बढ़ सकती है। क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सूखे का दौर आ सकता है। इससे जंगलों में आग लगने का खतरा भी बढ़ेगा। यह अनुमान नेपाल और भूटान में बेहद नुकसानदायक मानसून के बाद आया है।



सुपर-डुपर अल नीनो का अलर्ट, धरती लाल दिखी थी

8 अक्टूबर को आई शिकागो यूनिवर्सिटी के क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब के शोधकर्ताओं की रिपोर्ट में कहा गया था- दुनिया इस समय बेहद ताकतवर अल नीनो का सामना कर रही है। प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र का तापमान सामान्य से 3.4 फीसदी ज्यादा हो गया है। यह 1950 के बाद का सबसे खतरनाक अल नीनो बताया जा रहा है। मौसम विशेषज्ञ इसे 'सुपर-डुपर अल नीनो' कह रहे हैं। इससे दुनिया के कई हिस्सों में ज्यादा गर्मी, सूखा या भारी बारिश हो सकती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, इस अल नीनो से दुनियाभर में अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं।

हरि-हर मिलन! चांदी की पालकी में गोपाल मंदिर पहुंचे महाकाल

तुलसी-बिल्वपत्र की मालाओं से हुआ सृष्टि की सत्ता का हस्तांतरण

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजन-अभिषेक, अद्भुत रहा संगम

उज्जैन (एजेंसी)। उज्जैन में रविवार आधी रात शैव और वैष्णव परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। भगवान महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर शाही ठाठ-बाट के साथ गोपाल मंदिर पहुंचे। यहां भगवान द्वारकाधीश और बाबा महाकाल का हरि-हर मिलन हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोनों देवताओं का विशेष पूजन-अभिषेक किया गया। परंपरा के अनुसार, भगवान महाकाल ने बिल्वपत्र की माला भगवान विष्णु को अर्पित की, जबकि भगवान द्वारकाधीश ने तुलसी की माला महाकाल को पहनाई। इसी के साथ चार महीने तक भगवान शिव के पास रही सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी पुनः भगवान विष्णु को सौंपने का प्रतीकात्मक विधान पूरा हुआ।



चार महीने तक महाकाल संभालते हैं सृष्टि का भार

पौराणिक मान्यता के अनुसार, देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद चार महीने तक सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव संभालते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के बाद कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की रात भगवान महाकाल गोपाल मंदिर पहुंचकर उन्हें सृष्टि के संचालन का दायित्व सौंपते हैं। इसी परंपरा को हरिहर मिलन कहा जाता है। उज्जैन में वर्ष में एक बार होने वाले इस आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। गोपाल मंदिर के पुजारी मधुर शर्मा ने बताया कि हरिहर मिलन उज्जैन की वर्षों पुरानी अद्भुत परंपरा है। इसे शहर के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल किया जाता है।

बीजेपी विधायक रेखा पात्रा ने खाया जहर, हालत गंभीर

कोलकाता में भर्ती, संदेशखाली आंदोलन से चर्चा में आईं बंगाल दौरे में पीएम मोदी ने कहा था-आप शक्ति स्वरूपा

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की बीजेपी विधायक रेखा पात्रा ने जहर खा लिया है। दो दिनों से कोलकाता के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल के मुताबिक, रेखा पहले वेंटिलेटर पर थीं। सोमवार सुबह उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया है। हालांकि, उनके शरीर में जहर का असर बना हुआ है, जिसके कारण हार्ट रेट सामान्य से ज्यादा है। परिवार के मुताबिक, रेखा ने शनिवार रात हर्बल कीटनाशक खाया था। उनके पति संदीप पात्रा ने बताया कि रेखा की स्थिति ठीक नहीं है। अभी कुछ कहना संभव नहीं है।' रेखा पात्रा 2024 में संदेशखाली आंदोलन के दौरान चर्चा में आई थीं। 26 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने रेखा से फोन पर बातचीत की थी। मोदी ने कहा था- रेखा, आपने संदेशखाली में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। आप एक तरह से शक्ति स्वरूपा हैं।



तीन अस्पतालों में इलाज चला शरीर में ट्यूब डाली गई

पार्टी के मुताबिक, शनिवार रात करीब 9 बजे हिंगलगंज स्थित घर पर रेखा की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया था। फिर बशीरहाट सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां भी करीब चार घंटे इलाज के बावजूद उनकी हालत में खास सुधार नहीं हुआ।

पॉवर अपनी बढ़ती ताकत का दुनिया ने माना लोहा

भारत एशिया में तीसरा सबसे ताकतवर देश

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत एशिया में सबसे ज्यादा प्रभाव रखने वाले देशों में तीसरे नंबर पर है। उसने हाल ही में अपनी स्थिति और मजबूत की है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स

2026 में पावर स्कोर बढ़कर 40.5 अंक हुआ

2026 में भारत का कुल पावर स्कोर बढ़कर 40.5 अंक हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में भारत का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ा है। इसमें कूटनीतिक स्थिति, रक्षा सहयोग, सांस्कृतिक पहुंच और भविष्य के संसाधनों में सुधार का योगदान रहा। लिस्ट में अमेरिका पहले और चीन दूसरे नंबर पर है। भारत की



आर्थिक क्षमता का स्कोर घटकर 26.4 अंक हुआ, फिर भी वह इस श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहा।

रिपोर्ट में आर्थिक क्षमता में गिरावट का दावा- लोवी इंस्टीट्यूट ने भारत की आर्थिक क्षमता में गिरावट की वजह कमजोर रुपए और अर्थव्यवस्थाओं को मापने की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बदली पद्धति को बताया। भारत के विदेशों में निवेश में करीब 20 अरब डॉलर की कमी का भी उसके प्रदर्शन पर असर पड़ा। इसके बावजूद, भारत के भविष्य के संसाधनों का स्कोर बढ़कर 56.2 अंक हो गया। यह सुधार बेहतर आर्थिक अनुमान और देश के सामने मौजूद अवसरों को दिखाता है। रिपोर्ट ने कहा गया कि 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था और कूटनीति के नतीजे मिले-जुले रहे, लेकिन एशिया में उसका प्रभाव बढ़ा। कूटनीतिक प्रभाव भारत का सबसे मजबूत क्षेत्र बना रहा। इस श्रेणी में भारत को 70.3 अंक मिले। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्रीय नेतृत्व के आंकलन में बड़ा सुधार हुआ। वह तीन स्थान ऊपर पहुंचे और चीनी रापति शी जिनपिंग के बाद दूसरे सबसे प्रभावी क्षेत्रीय नेता बने। भारत ने अपने आर्थिक रिश्तों में भी सुधार किया। वह इस श्रेणी में दो स्थान ऊपर उठकर सातवें स्थान पर पहुंचा। क्षेत्रीय व्यापार और निवेश संबंधों में अपेक्षाकृत स्थिरता आई है।

रक्षा और सांस्कृतिक प्रभाव में बढ़ोतरी

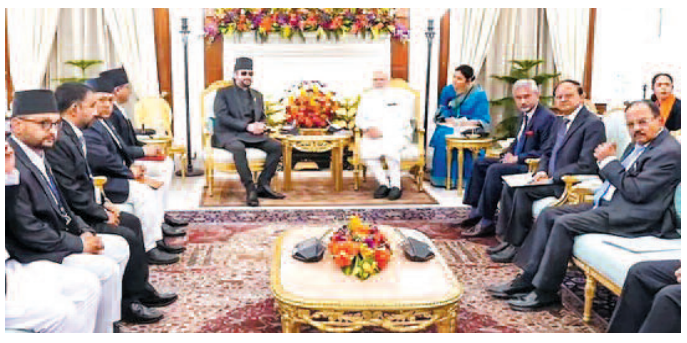
भारत का रक्षा नेटवर्क स्कोर बढ़कर 18.6 अंक हो गया। वह इस श्रेणी में नौवें स्थान पर पहुंचा। इस सुधार को क्षेत्रीय रक्षा सहयोग में बढ़ोतरी और दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री से मदद मिली। भारत का सांस्कृतिक प्रभाव स्कोर भी बढ़कर 43.8 अंक हो गया। सांस्कृतिक पहुंच, जनसंपर्क और लोगों के बीच संपर्क के सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ। इन सुधारों से 2023 के बाद पहली बार भारत के उपलब्ध संसाधनों और एशिया में उसके प्रभाव के बीच का अंतर कम हुआ। भविष्य के संसाधनों में बढ़ोतरी के साथ यह संकेत मिला कि भारत अपना बढ़ता क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रख सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की कुल शक्ति भारत से अब भी 80 फीसदी ज्यादा है। इससे दोनों देशों के बीच जारी अंतर साफ होता है। 2026 का एशिया पावर इंडेक्स 27 देशों और क्षेत्रों का आंकलन करता है।

नेपाल को 15 हजार करोड़ की मदद

पीएम मोदी बोले-नेपाल के बिना हमारे धाम और राम दोनों अधूरे

बालेन बोले-नेपाल और भारत के रिश्ते हिमालय की तरह मजबूत

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेपाल के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के लिए 15 हजार करोड़ भारतीय रुपए की मदद का ऐलान किया। बालेन शाह के भारत के पहले द्विपक्षीय दौरे को दोनों देशों की गहरी दोस्ती का प्रतीक बताते हुए मोदी ने साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम और माता सीता भारत-नेपाल की साझा सभ्यता के प्रतीक हैं। 2018 में जनकपुर यात्रा को याद करते हुए मोदी ने कहा कि नेपाल के बिना हमारे धाम अधूरे हैं और नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। वहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने की बात कही। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के रिश्ते हिमालय की तरह मजबूत और समुद्र की तरह विशाल हैं।



नेपाल को कांडला-पारादीप बंदरगाहों तक पहुंच मिली- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत नेपाल को गुजरात के कांडला और ओडिशा के पारादीप बंदरगाहों तक पहुंच देगा। इससे नेपाल का दूसरे देशों के साथ व्यापार आसान होगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ बेहतर व्यापार और निवेश से नेपाल की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सड़क और सीमा संपर्क को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच धारचूला में सड़क पुल का उद्घाटन किया गया है। साथ ही बनबसा में एकीकृत जांच चौकी की आधारशिला रखी गई है। मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से उत्तराखंड और नेपाल के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही आसान होगी।

मोदी बोले-

नेपाल के बिना हमारा धाम भी अधूरा है

मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सिर्फ पड़ोसी देशों का रिश्ता नहीं है, बल्कि दोनों का इतिहास, संस्कृति और परंपराएं भी एक-दूसरे से जुड़ी हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच सदियों पुराने रिश्ते हैं। उन्होंने 2018 में अपनी जनकपुर यात्रा को याद करते हुए कहा कि भारत और नेपाल का संबंध भगवान राम और माता सीता से भी जुड़ा है। जनकपुर को माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है, जबकि अयोध्या भगवान राम की नगरी है। दोनों जगहों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी रिश्ते का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, नेपाल के बिना हमारा धाम भी अधूरा है। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के संबंधों की यही खासियत दोनों देशों को करीब लाती है।

योगी बोले-

सदियों पुराना सांस्कृतिक रिश्ता फिर जुड़ा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरयू-कमला एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू होने से अयोध्या और मिथिला के बीच सदियों पुराना सांस्कृतिक रिश्ता एक बार फिर मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन सेवा से दोनों देशों के श्रद्धालुओं के लिए सीधे यात्रा करना आसान हो जाएगा। नेपाल के श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या आ सकेंगे, वहीं भारत के श्रद्धालु देवी जानकी की पूजा के लिए जनकपुरधाम जा सकेंगे।

भारत-नेपाल के बीच 200 किमी का चक्कर खत्म

भारत और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को अब करीब 200 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी और बालेन शाह ने दिल्ली से बटन दबाकर काली नदी पर बने छारछुम अंतरराष्ट्रीय मैत्री मोटर पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह पुल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला को नेपाल के दार्चुला से जोड़ेगा। इससे दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों के लोगों की आवाजाही आसान होगी। अब तक लोगों को एक-दूसरे के यहां जाने के लिए करीब 200 किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ता था। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पुल शुरू होने से भारत और नेपाल के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। उद्घाटन के दौरान छारछुम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुटे। समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य कर इस मौके का जश्न मनाया।

सीजेआई सूर्यकांत की न्यायिक अधिकारियों को बड़ी फटकार

कहा-हमें पता है दिन भर क्या करते हैं, बस 24 घंटे सुविधाएं चाहिए



सिर्फ अपने लिए सोचते रहते हैं अधिकारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत ने सोमवार को कुछ न्यायिक अधिकारियों के रवैये पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उनका कहना है कि ऐसे अधिकारी अपने अदालती कार्यों पर ध्यान देने के बजाए, सिर्फ अपने ही लाभ के बारे में सोचते रहते हैं और समय बिता देते हैं। जबकि, अदालतों के बाहर लोग कतारें लगाए खड़े रहते हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने कुछ न्यायिक अधिकारियों द्वारा अपनी सर्विस और रिटायरमेंट के बाद के लाभों से जुड़े विषयों पर बार-बार अदालतों का चक्कर काटने के बर्ताव के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे अधिकारियों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी पता नहीं है कि उनका दिनभर क्या चलता रहता है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, अब वे कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। हर चीज में न्यायिक अधिकारी आवेदन लगा रहे हैं (यह कहते हुए) कि यह मंजूरी दी जाए।

एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं है कि नीचे क्या चल रहा है। न्यायिक अधिकारी 24 घंटे सिर्फ अपने फायदे और रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में सोचते रहते हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने यह टिप्पणी ए जुबिया बनाम केरल हाई कोर्ट से जुड़े एक केस की सुनवाई के दौरान की है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच में यह सुनवाई जिला न्यायपालिका में भर्तियों के मामले को लेकर चल रही है। सीजेआई सूर्यकांत ने भारत के चीफ जस्टिस के रूप में अपने अब तक के करीब एक साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं, जो सुर्खियां बनी हैं- हाल ही में सीजेआई ने कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों को संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संसद का मानसून सत्र बना इतिहास का नया रिकॉर्ड

(लेखक - विनोद सिंह, 'तकियावाला')

100 दिन बाद भी नहीं हुआ सत्रावसानसंवैधानिक प्रावधानों के दायरे में जारी संसदीय प्रक्रिया ने खड़े किए कई अहम सवाल; महिला आरक्षण, परिसीमन और लोकसभा की बढ़ती सदस्य संख्या पर विशेष बैठक की संभावनाओं के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति की चुनौती

भारतीय संसदीय इतिहास में 21 नवंबर 2026 की तारीख एक अलग वजह से दर्ज हो गई। संसद का मानसून सत्र समाप्त हुए बिना ही 100 दिन की अवधि पार कर गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन राष्ट्रपति की ओर से अब तक औपचारिक सत्रावसान की अधिसूचना जारी नहीं हुई।इस प्रकार संसद का मानसून सत्र पिछले 87 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक नए ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुँच गया। वर्ष 2008 में संसद का एक सत्र 87 दिनों तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ था। इस बार यह अवधि 100 दिनों तक पहुँच गई है। पहली नजर में यह स्थिति सामान्य संसदीय परंपरा से अलग दिखाई देती है। आमतौर पर संसद का कोई सत्र समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान की घोषणा की जाती है और उसके बाद अगले सत्र की तारीख तय होती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि संविधान और संसदीय प्रक्रिया की बारीकियों को समझना आवश्यक है। स्थगन और सत्रावसान में अंतर समझना जरूरी भारतीय संविधान में संसद की कार्यवाही को लेकर स्पष्ट प्रावधान हैं।संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को समय-समय पर आहूत करने का अधिकार देता है। इसके साथ यह अनिवार्य व्यवस्था भी है कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद नियमित रूप से काम करे और सरकार विधायिका के प्रति जवाबदेह बनी रहे। यहाँ तीन संसदीय शब्दों का अंतर समझना आवश्यक है। पहला, स्थगन यानी एडजर्नमेंट, जिसमें सदन की बैठक कुछ समय के लिए रोक दी जाती है। दूसरा, अनिश्चितकालीन स्थगन यानी एडजर्नमेंट साइन डाई, जिसमें सदन की अगली बैठक की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं होती। तीसरा, सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति के आदेश से संसद के चल रहे सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त किया जाता है। इसलिए 13 अगस्त को संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने का अर्थ यह नहीं था कि मानसून सत्र संवैधानिक रूप से समाप्त हो गया था। जब तक राष्ट्रपति सत्रावसान का आदेश जारी नहीं करते, तब तक सत्र औपचारिक रूप से जारी रह सकता है। लोकसभा सचिवालय की संसदीय प्रक्रिया संबंधी जानकारी में भी इन तीनों व्यवस्थाओं के बीच स्पष्ट अंतर बताया गया है। क्या 100 दिनों तक सत्रावसान नहीं होना असंवैधानिक है? इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पक्ष यही है। सामान्य धारणा के विपरीत संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद संसद का सत्र कितने दिनों के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए। अर्थात 100 दिन तक सत्रावसान नहीं होना अपने आप में संविधान का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी स्पष्ट कर चुके हैं कि अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद सत्रावसान के लिए संविधान में कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं है। उन्होंने पूर्व के संसदीय उदाहरणों का उल्लेख करते हुए इसे संवैधानिक अथवा प्रक्रियागत अनियमितता मानने से इनकार किया था। हालाँकि, संवैधानिक वैधता और संसदीय परंपरा दो अलग-अलग विषय हैं। किसी प्रक्रिया का संविधानसम्मत होना यह आवश्यक नहीं बनाता कि उसके राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रभावों पर सवाल न उठाए जाएँ। संसद जनता के प्रतिनिधियों की सर्वोच्च विधायी संस्था है। इसलिए उसकी कार्यवाही की नियमितता, पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। महिला आरक्षण और परिसीमन बना चर्चा का केंद्र मानसून सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं होने के पीछे सबसे अधिक चर्चा महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन की है। महिला आरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर लोकसभा की सदस्य संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का विषय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है। लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया परिसीमन से जुड़ी हुई है। ऐसे में परिसीमन का प्रश्न केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के विभिन्न राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संघीय संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। लोकसभा की वर्तमान निर्वाचित सदस्य संख्या 543 है। प्रस्तावित परिसीमन व्यवस्था के संदर्भ में इसे अधिकतम 850 तक बढ़ाने की संभावना पर चर्चा हुई है। इस विषय पर दक्षिण भारतीय राज्यों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी चिंताएँ व्यक्त की हैं। उनका प्रमुख प्रश्न यह है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण से राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन किस प्रकार प्रभावित होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि 17 अप्रैल 2026 को परिसीमन और महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक समर्थन प्राप्त नहीं कर सका था। इसके बाद इस विषय पर राजनीतिक सहमति बनाने की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। विशेष सत्र की संभावना और विपक्ष की भूमिका मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं होने से यह संभावना बनी हुई है कि आवश्यकता पड़ने पर उसी सत्र की आगे की बैठक बुलाई जा सकती है। संसदीय प्रक्रिया के अनुसार अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद भी लोकसभा को पुनः बैठक के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक बार नया सत्र शुरू करने की अनिवार्यता नहीं होती। हालाँकि विशेष सत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक और सार्वजनिक विमर्श में अधिक होता है। संविधान में इसे अलग प्रकार के सत्र के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। संसद की बैठक बुलाने का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 85 ही है। इस बीच विपक्षी दलों ने परिसीमन के प्रस्तावों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने और विधेयक के प्रारूप पर व्यापक चर्चा कराने की माँग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस विषय पर राजनीतिक दलों के साथ संवाद की आवश्यकता जताई है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वह विपक्ष से सहयोग और सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। यहाँ यह समझना होगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया सामान्य विधायी प्रक्रिया से अलग है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता होती है। कुछ विषयों से संबंधित संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति भी जरूरी होती है। इसलिए परिसीमन जैसे संवेदनशील विषय पर व्यापक राजनीतिक सहमति का विशेष महत्व है। संसदीय लोकतंत्र की असली कसौटी भारतीय लोकतंत्र की शक्ति केवल चुनाव कराने या बहुमत के आधार पर सरकार चलाने में नहीं, बल्कि विभिन्न विचारों, क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों को विधायी प्रक्रिया में उचित स्थान देने में निहित है। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक जिम्मेदारियाँ हैं। सरकार का दायित्व है कि वह महत्वपूर्ण विधेयकों पर पर्याप्त जानकारी और चर्चा का अवसर उपलब्ध कराए। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह रचनात्मक बहस के माध्यम से नीतियों की कमियों को सामने लाए और जनहित के मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह बनाए। संसद का मानसून सत्र 100 दिनों तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं होना निश्चित रूप से संसदीय इतिहास की उल्लेखनीय घटना है। लेकिन इस रिकॉर्ड का वास्तविक महत्व केवल दिनों की गिनती में नहीं है। इसका महत्व इस बात में है कि संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संसद किस प्रकार देश के महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक प्रश्नों का समाधान तलाशती है। महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे विषय आने वाले वर्षों में भारतीय लोकतंत्र की दिशा तथा संघीय ढाँचे को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इन पर जल्दबाजी के बजाय व्यापक विमर्श, पारदर्शिता और संवैधानिक मर्यादा के साथ निर्णय लेना आवश्यक है। संसद की गरिमा तभी सुरक्षित रह सकती है, जब वहाँ मतभेदों को टकराव के बजाय संवाद का माध्यम बनाया जाए। अंततः संसद का वास्तविक रिकॉर्ड दिनों की संख्या से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास, लोकतांत्रिक जवाबदेही और संविधान की भावना के अनुरूप लिए गए निर्णयों से तय होगा।

(स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तम्भकार)

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

यमुना भी मैली

पिछले दिनों दिल्ली के यमुना तटों पर छठ पर्व के मौके पर रासायनिक झाग के बीच सूर्य को अर्घ्य देती महिला श्रद्धालुओं की तस्वीरों ने पूरे देश को विचलित किया। तंत्र की काहिली देखिए कि पर्व के दौरान भी श्रद्धालुओं को प्रदूषण मुक्त पानी वाले घाट नहीं मिल सके। लेकिन अब यमुना के पानी को जहरीले रसायनों वाले झाग से मुक्त करने के दावे किए जा रहे हैं। यह विडंबना ही है कि हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद यमुना और मैली हो गई है। मैली यमुना फैक्ट्री मालिकों और लोगों की आपराधिक लापरवाही तथा तंत्र की काहिली की दास्तां बयां करती है। यही वजह है कि पिछले दिनों देश की शीर्ष अदालत ने यमुना नदी में गिरने वाले 520 नालों और सफाई के सरकारी प्रयासों पर सवाल उठाए हैं। विडंबना यही है कि जब तक कोई राजनीतिक दल विपक्ष में होता है, तब तक अपनी सुविधा के हिसाब से यमुना की सफाई पर सवाल उठाता है, लेकिन जब वही राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो खामोशी ओढ़ लेता है। बहरहाल, पिछले कई दशकों से यमुना के प्रदूषित होने का प्रश्न पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी सार्वजनिक बहसों के केंद्र में रहा है। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए यह चुनाव की दृष्टि से सुविधा का मुद्दा ही रहा है। विपक्ष में हैं तो यमुना की सफाई को मुद्दा बनाया जाता है। सत्ता में आते ही चुप्पी साध ली जाती है। जाहिर है, इसकी सफाई के लिए ईमानदार प्रयास होते ही नहीं। यदि होते तो यमुना की यह दुर्दशा ही न होती। मौलिक सवाल यही है कि यदि यमुना की सफाई में हजारों करोड़ रुपये खर्च हुए हैं तो यमुना मैली की मैली क्यों है? आज वह दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में क्यों शामिल है? सवाल सरकारों की इच्छाशक्ति का भी है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यमुना की दुर्दशा पर लगातार सवाल उठाए हैं। शीर्ष अदालत ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि यमुना की सफाई पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद प्रदूषण पहले के मुकाबले और कैसे बढ़ गया है? वह भारी-भरकम राशि कहां गई, जो सफाई पर खर्च की गई थी? आखिर क्या वजह है कि नदी का पानी उपयोग लायक नहीं रह गया? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी उल्लेख किया कि गंदा पानी ले जाने वाले 520 नाले यमुना में क्यों गिराए जा रहे हैं? कोर्ट ने प्रश्न किया कि जिन विभागों की जिम्मेदारी यमुना में गंदे नालों को जाने से रोकने की थी, उन्होंने क्या किया? यही वजह है कि अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और जनपदों में यमुना में गिरने वाले नालों की निगरानी की जाए। कोर्ट ने यमुना की सफाई के मुद्दे पर राजनीतिक दलों की सुविधा की राजनीति पर प्रश्न उठाए। अदालत ने इस मुद्दे पर सरकारों और राजनीतिक दलों को इच्छाशक्ति दर्शाने की नसीहत भी दी। बहरहाल, तंत्र की नाकामी के साथ-साथ नागरिक भी गैर-जिम्मेदार व्यवहार के लिए दोषी हैं। नागरिकों को आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए यमुना को साफ करने का बीड़ा उठाना चाहिए।

गुरु नानक देव ने फ़ैलाया जगत में ज्ञान का प्रकाश

(लेखक - डॉ. श्रीगोपाल नारसन)

अंधविश्वास और आडंबरों को दूर कर ज्ञान का प्रकाश सारे जगत में फैलाने वाले गुरु नानक का प्रकाश उत्सव यानि अवतरण दिवस कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, हालांकि उनका वास्तविक जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। गुरु नानक देव पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर एक किसान के घर जन्मे थे। उनके माथे पर शुरू से ही तेज आभा बनी हुई थी। तलवंडी जो अब पाकिस्तान के लाहौर से 30 मील दूर पश्चिम में स्थित है, गुरु नानक का नाम साथ जुड़ने के बाद ननकाना कहलाया। गुरु नानक के प्रकाश उत्सव पर प्रति वर्ष भारत से सिख श्रद्धालुओं का जत्था ननकाना साहिब जाकर वहां अरदास करता है।

बचपन में जब नानक देव के अन्य साथी बच्चे खेल कूद में व्यस्त होते थे तो वह अपने नेत्र बंद कर चिंतन मनन में खो जाते थे। यह देख उनके पिता कालू एवं माता तृप्ता चिंतित हो जाते थे। उनके पिता ने पंडित हरदयाल के पास उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा ,लेकिन पंडितजी बालक नानक के प्रश्नों पर निरुत्तर हो जाते और वे उनके ज्ञान व प्रतिभा को देखकर समझ गए कि नानक को स्वयं ईश्वर ने पढ़ाकर इस संसार में भेजा है। नानक को मौलवी कुतुबुद्दीन के पास पढ़ने के लिए भी भेजा गया लेकिन वह भी नानक के प्रश्नों से निरुत्तर हो गए। अन्ततः नानक देव ने घर बार छोड़ दिया और दूर देशों में भ्रमण करना शुरू किया। इससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। उन्होंने कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार पंजाब से आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदिगुरु बन हुए।

गुरु नानक देव का विवाह सन सन1485 में बटाला निवासी कन्या सुलक्खनी से हुआ। उनके दो पुत्र श्रीचन्द और लक्ष्मीचन्द हुए। गुरु नानक के पिता ने उन्हें कृषि, व्यापार आदि में लगाना चाहा किन्तु यह सारे प्रयास नाकाम साबित हुए। उनके पिता ने उन्हें घोड़ों का व्यापार करने के लिए जो राशि दी थी, वह भी नानक जी ने साधु सेवा में लगा दी। कुछ समय बाद नानक जी अपने बहनोई के पास सुल्तानपुर चले गये। वहां वे सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के यहां मादी रख लिये गये। नानक जी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते थे और जो भी आय होती थी, उसका ज्यादातर हिस्सा साधुओं और गरीबों को दे देते थे।

सिख ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि गुरु नानक नित्य बेई नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के पश्चात वन में अन्तर्ध्यान हो गये। उस समय उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया और कहाल मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, जो तुम्हारे सम्पर्क में आयेंगे वे भी आनन्दित होंगे। जाओ दान दो, उपासना करो, स्वयं नाम लो और दूसरों से भी नाम स्मरण कराओ। इस घटना के पश्चात वे अपने परिवार का भार अपने श्वसुर को सौंपकर विचरण करने निकल पड़े और धर्म का प्रचार करने लगे। उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही विदेशों की यात्राएं भी कीं और जन सेवा का उपदेश दिया। बाद में वे करतारपुर में आकर बस गये और सन1521 ई. से सन1539 ई. तक वहीं रहे।

गुरु नानक देव ने जातल्पांत को समाप्त करने और सभी को समान दृष्टि से देखने की दिशा में कदम उठाते हुए लंगर प्रथा शुरू की । लंगर में सब छोटेल्बड़े, अमीरल्गरीब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। आज भी गुरुद्वारों में उसी लंगर की व्यवस्था चल रही है, जहां हर समय हर किसी को भोजन उपलब्ध होता है। इस में सेवा और भक्ति का भाव मुख्य होता है। गुरु नानक देवजी का जन्मदिन प्रतिवर्ष गुरु पूर्व के रूप में मनाया जाता है। तीन दिन पहले से ही प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। जगहल्जगह भक्त लोग पानी और शरबत आदि की व्यवस्था करते हैं। गुरु नानक जी का निधन सन सन1539 ई. में हुआ। उन्होंने गुरुगद्दी का भार गुरु अंगददेव (बाबा लहना) को सौंप दिया थाऔर स्वयं करतारपुर में ज्योति में लीन हो गए।

गुरु नानक जी ने अपने अनुयायियों को दस उपदेश दिए जो कि सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे। गुरु नानक जी की शिक्षा का मूल निचोड़ यही है कि परमात्मा एक, अनन्त, सर्वशक्तिमान और सत्य है। वह सर्वत्र व्याप्त है।



नामल्स्मरण सर्वोपरि तत्व है और नाम गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु नानक की वाणी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ओतल्प्रोत है। उन्होंने अपने अनुयायियों को जीवन की दस शिक्षाएं दीं जो यहां प्रस्तुत हैं,

ईश्वर एक है,सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है। ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता ईमानदारी से और मेहनत कर के उदरपूर्ति करनी चाहिए। बुरा कार्य करने के बारे में न सोचें और न किसी को सताएं। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से ज़रूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए। सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। भोजन शरीर को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है पर लोभल्लालच व संग्रहवृत्ति बुरी है।गुरु नानक देव की दी हुई शिक्षा से समाज मे व्यापक जागृति आई और वे सिर्फ सिख धर्म ही नही सम्पूर्ण समाज के प्रेरक बने।

(लेखक आध्यात्मिक चिंतक व विक्रमशीला हिंदी विद्यापीठ के उपकुलपति है)



अहिंसा का स्वरूप

सामान्यतः अहिंसा को निषेधार्थक माना जाता है। 'न हिंसा - अहिंसा'- हिंसा का अभाव अहिंसा है, यह इसकी एकांगी परिभाषा है। इसको सर्वांगीण रूप से परिभाषित करने के लिए इसके विधेयार्थ और निषेधार्थ दोनों को समझना जरूरी है। किसी प्राणी के प्राणों का वियोजन नहीं करना, इस सूत्र का हिंसा के संदर्भ में जितना मूल्य है, उससे भी अधिक मूल्य है किसी भी प्राणी के प्रति अनिष्ट चिंतन के बहिष्कार का।

असत् विचार हिंसा है। असत् वचन सा है। जितना कुछ झूठ बोला जाता है, वह हिंसा की प्रेरणा से ही बोला जाता है। असत् चिंतन और असत् वाणी की तरह असत् व्यवहार मात्र हिंसा है, चाहे वह किसी के भी प्रति हो। मनुष्य की प्रवृत्ति सत् और असत् दोनों प्रकार की होती है। जिस प्रवृत्ति के साथ असत् शब्द का योग हो जाता है, वह हिंसा-संवलित ही होती है।

दूसरों के प्रति द्वेष की भावना, ईर्ष्या, उन्हें गिराने का मनोभाव और उनकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को रोकने के सारे प्रयत्न हिंसा में अंतर्गर्भित हैं। दूसरों के मन में भय उत्पन्न करना, उनके सामने दुखद परिस्थितियां उभार देने, उनके विकास के मार्ग में बाधा पहुंचाना आदि प्रवृत्तियां भी हिंसा की परिधि में समाविष्ट हैं। इन प्रवृत्तियों का सर्वथा निरोध अहिंसा का आदर्श है। यह अहिंसा का नेगेटिव पक्ष है।

अपने पॉजिटिव पक्ष में अहिंसा समता, मैत्री, संयम आदि उदात्त वृत्तियों से अनुबंधित है। यहां अहिंसा का वाच्यार्थ न मारने तक की सीमा में आबद्ध नहीं है। जहां यह प्रतिबद्धता जुड़ जाती है, अहिंसा का व्यापक अर्थ एक छोटे-से संदर्भ में समा जाता है। समता का धरातल असीम है। मैत्री की पौध इसी धरातल पर फली-फूली रह सकती है। इससे आत्मौपम्य की भावना जागृत होती है। आत्मतुला की बुद्धि से प्रेरित व्यक्ति कही अहिंसा को समझ सकता है और उसका पालन कर सकता है। जो व्यक्ति छोटे और बड़े, अनुकूल और प्रतिकूल हर प्राणी के प्रति समत्व बुद्धि का विकास करता है, वह अहिंसक होता है।

विचार मंथन

डिग्री या हुनरः युवाओं के भविष्य की जवाबदेही पर सरकार की भूमिका?

(लेखक- सनत जैन / ईएमएस)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, आने वाला समय हुनरमंद लोगों का होगा। भविष्य में कागजी डिग्रियों और सर्टिफिकेट के आधार पर रोजगार, नौकरी या सफलता नहीं मिलेगी, जिन युवाओं के पास व्यावहारिक कौशल होगा, वही रोजगार और आर्थिक समृद्धि हासिल कर सकेंगे। उन्होंने आईआईटी और आईटीआई को समान महत्व देने की बात कहकर कौशल आधारित शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते प्रभाव के बीच उन्होंने यह भी कहा, एआई का कौशल रखने वाले युवाओं से रोजगार कोई नहीं छीन सकता। प्रधानमंत्री की यह बात सुनने में आकर्षक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप जरूर लगती है, लेकिन इसके साथ कई गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। भारत में पिछले तीन दशकों से शिक्षा को रोजगार का प्रमुख आधार माना जाता रहा है। करोड़ों युवाओं ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग और पीएचडी जैसी उच्च डिग्रियां हासिल करने के लिए वर्षों मेहनत की है। अभिभावकों ने अपनी जमा पूंजी और बैंक से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा पर खर्च की हैं। इसके बावजूद करोड़ों की संख्या में शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। ऐसे में जब देश का प्रधानमंत्री डिग्री और सर्टिफिकेट की तुलना में हुनर को अधिक महत्वपूर्ण बताता है, तो स्वाभाविक रूप से युवाओं के मन में यह सवाल उठता है, क्या उनकी वर्षों की मेहनत और शिक्षा का कोई मूल्य नहीं रह गया है? वह किसी काम का नहीं है।

दरअसल, समस्या डिग्री और हुनर के बीच तुलना करने की नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और रोजगार बाजार के बीच बढ़ते अंतर को समझने की है। किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था के लिए उच्च शिक्षा और तकनीकी कौशल दोनों जरूरी हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, शोधकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी तैयार करने के लिए विश्वविद्यालयों की भूमिका को कम नहीं किया जा सकता। वहीं आईटीआई और कौशल प्रशिक्षण संस्थान उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित कामगार तैयार करते हैं। दोनों की अपनी अलग उपयोगिता है। आईआईटी और आईटीआई को एक-दूसरे का विकल्प बताने के बजाय इन्हें शिक्षा व्यवस्था के पूरक संस्थानों के रूप में विकसित करना सरकार की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा सवाल सरकार की शिक्षा नीति और उसकी जवाबदेही का है। पिछले 12 वर्षों में नई शिक्षा नीति, कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और डिजिटल शिक्षा जैसी कई योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। सरकार ने युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम शुरू किए। इसके बावजूद शिक्षित बेरोजगारी और डिग्रीधारी युवाओं की नौकरी एवं रोजगार संबंधी परेशानियां चिंता का विषय बनी हुई हैं। सवाल यह है कि इन योजनाओं से कितने युवाओं को वास्तविक रोजगार मिला? क्या सरकार की योजनाएं सही थी? सरकार ने जो योजनाएं बनाई थीं क्या उसका क्रियान्वय धरातल पर हुआ है? कितने प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक मशीनें, प्रशिक्षक और उद्योगों के अनुरूप पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं? प्रशिक्षण के बाद युवाओं को कितने स्थायी रोजगार मिले, कितनों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता मिली? इस सच्चाई को सभी जानते हैं, लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे की तरह उपदेश देने में सभी माहिर हैं। एआई और नई तकनीक के दौर में कौशल विकास की आवश्यकता और बढ़ गई है। हर युवा को एआई विशेषज्ञ बना देना संभव नहीं है। इसके लिए डिजिटल सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, आर्थिक संसाधन और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने होंगे। केवल युवाओं से हुनरमंद बनने की अपेक्षा करना ठीक नहीं है। सरकार को उद्योगों के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को रोजगार मिले।

प्रधानमंत्री की चुनौती स्वीकार करने वाली सोच का स्वागत किया जा सकता है, लेकिन युवाओं की चुनौती भी सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। उन्हें बताना होगा, शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार की गारंटी नहीं तो कम से कम रोजगार के पर्याप्त अवसर कैसे उपलब्ध होंगे। शिक्षा नीति के परिणामों का मूल्यांकन, कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता और रोजगार सृजन के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए। सरकार वास्तविक स्थिति को क्यों छुपा कर रखती है? आज की युवा पीढ़ी सरकार से केवल प्रेरक भाषण नहीं, बल्कि ठोस जवाब चाहती है। वह जानना चाहती है, डिग्री हासिल करने के बाद उसका भविष्य क्या होगा? यदि डिग्री में कोई भविष्य नहीं है तो इसमें कोई बदलाव क्यों नहीं किया गया। हुनर सीखने के लिए आवश्यक संसाधन कौन उपलब्ध कराएगा?

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

एटेरो खनिज कारोबार में 3,000 करोड़ का निवेश करेगी

नई दिल्ली ।

ई-कचरा पुनर्चक्रण कंपनी एटेरो की अपने खनिज निष्कर्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए अगले पांच वर्षों में 3,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। एटेरो के एक अे धिकारी ने बताया कि कंपनी अगले चार वर्षों में अपनी कुल ई-कचरा पुनर्चक्रण क्षमता को चार गुना से अधिक बढ़ाकर 10 लाख टन करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि हम खास तौर पर अगले पांच वर्षों में महत्वपूर्ण खनिज संयंत्र के विस्तार में करीब 3,000 करोड़ रुपये का निवेश करने पर विचार कर रहे हैं। इसका लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा लिथियम, निकेल में जाएगा। एटेरो का दावा है कि वह सोना, चांदी, तांबा, एल्युमीनियम, निकेल, लिथियम, कोबाल्ट और नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम जैसे दुर्लभ पृथ्वी खनिजों सहित 22 से अधिक महत्वपूर्ण खनिज निकालती है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा पुनर्चक्रण की हमारी मौजूदा क्षमता लगभग 2,25,000 टन सालाना है। हम अगले चार वर्षों में इसे बढ़ाकर 10 लाख टन करना चाहते हैं। हम अगले चार वर्षों में अपने लिथियम और बैटरी पुनर्चक्रण संयंत्र को भी लगभग पांच गुना बढ़ा रहे हैं।

साइबर बीमा को स्मार्ट बनाए भारत- डेलॉयट इंडिया

एआई हमलों से निपटने के लिए वास्तविक समय आधारित जोखिम आकलन जरूरी

नई दिल्ली ।

भारत में बढ़ते डिजिटल जोखिमों के बीच डेलॉयट इंडिया ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट डिफेंडिंग द डिजिटल इंश्योरर में देश की साइबर बीमा कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का आह्वान किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पारंपरिक तरीकों को छोड़ अब उन्हें वास्तविक समय की साइबर खतरे की खुफिया जानकारी पर आधारित जोखिम आकलन अपनाने की सख्त जरूरत है। डेलॉयट ने चेताया है कि साइबर हमलों के बढ़ते दायरे और डिजिटल तंत्र के तेजी से फैलने के कारण पारंपरिक जोखिम आकलन पुराने पड़ गए हैं। कृत्रिम मेधा (एआई) संचालित हमलों की तीव्र गति का मुकाबला करने में मौजूदा तरीके अक्षम साबित हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सटीक प्रीमियम और बीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनियों को अब साइबर खतरे की खुफिया जानकारी, व्यवहार संबंधी मानकों और विभिन्न आंकड़ों को शामिल करना होगा। एआई इस बदलाव को और तेज कर रहा है, जिससे स्वचालित धोखाधड़ी और एआई-संचालित हमलों में 1,200 फीसदी से अधिक की वृद्धि देखी गई है। डेलॉयट दक्षिण एशिया में बीमा क्षेत्र के एक अे धिकारी ने बताया कि भारत का साइबर बीमा बाजार देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था और बढ़ते साइबर जोखिम की तुलना में अभी भी छोटा है। हालांकि वर्तमान में मुख्य रूप से वित्तीय संस्थान और बड़े उद्यम इसे अपना रहे हैं, भविष्य में इसकी वृद्धि डिजिटल भुगतान, क्लाउड प्लेटफॉर्म और आपस में जुड़े तंत्र पर निर्भर छोटे-बड़े व्यवसायों से आने की प्रबल संभावना है।

चाय उद्योग को मिलेगी नई गति, सरकार निर्यात व गुणवत्ता पर केंद्रित

वाणिज्य मंत्री ने हितधारकों के साथ किया अहम मंथन

नई दिल्ली ।

भारत, जो दुनिया में काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक निर्यातक है, अपने चाय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पश्चिम बंगाल के कुर्सेओंग में चाय उद्योग के हितधारकों के साथ एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, गुणवत्ता में सुधार करना और चाय श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने 988.13 मिलियन डॉलर मूल्य की 282.11 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया था।

यह क्षेत्र देश की कृषि अर्थव्यवस्था और निर्यात आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दार्जिलिंग चाय उद्योग के पुनरुद्धार, चाय नीलामी प्रणाली को और अधिक प्रभावी, तेज़ तथा पारदर्शी बनाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

वाणिज्य मंत्री ने चाय अनुसंधान को सुदृढ़ करने, गुणवत्ता में सुधार लाने और एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (ईपीएम) के तहत निर्यात को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। हितधारकों के साथ व्यापार करने में आसानी को प्राथमिकता बनाते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और दक्षता बढ़ाने पर भी सहमति बनी, जिसमें तकनीक-आधारित सुधारों और परिचालन दक्षता में वृद्धि पर बल दिया गया।

शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद,निवेशकों के 6 लाख करोड़ डूबे

सेंसेक्स 1483, निफ्टी 434 अंक गिरा

मुम्बई ।

घरेलू शेयर बाजार सोमवार को भारी गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हाव होने से बाजार टूटा। आज कारोबार के दौरान बैंकिंग शेयरों को जबरदस्त नुकसान हुआ। इसके अलावा मेटल और ऑयल व गैस शेयरों में बिकवाली से भी बाजार नीचे आया। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1,483.72 अंक टूटकर 82,435.99 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला, एनएसई निफ्टी 434.20 अंक की गिरावट के साथ ही 25,366.40 के स्तर के नीचे आ गया। बाजार की इस भारी गिरावट से बाजार पूंजीकरण में 6 लाख करोड़ से भी अधिक का नुकसान हुआ। बाजार के व्यापक रुझान पर नजर डालें तो गिरावट वाले शेयरों की संख्या तेजी वाले शेयरों से कहीं ज्यादा रही। एक्सचेंज पर कुल 2,687 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि केवल 1,450 शेयरों में तेजी देखी गई और 199 शेयर सपाट रहे। इसके अलावा, निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में भी 0.7-0.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जो बताता है कि बिकवाली का दबाव सभी स्तरों पर था।



लगभग सभी प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा मार निफ्टी मेटल पर पड़ी। आज दिग्गज शेयरों में आई जबरदस्त बिकवाली ने निवेशकों को खासा नुकसान पहुंचाया। टाटा स्टील 8.43 फीसदी की भारी गिरावट के साथ सबसे अधिक नुकसान में रहा। इसके अतिरिक्त, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक , हिंडाल्को , एसबीआई , कोटक बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भी गिरावट रही। वहीं इस बड़ी गिरावट के बीच कुछ खास शेयरों में खरीददारी हावी रही। टीसीएस 3.53 फीसदी की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुआ।

डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे टूटकर 92.85 पर खुला

रुपया शुक्रवार को 70 पैसे मजबूत होकर 92.62 पर बंद हुआ था



मुंबई ।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को रुपया 93.47 पर खुला और 92.43 तक मजबूत होने के बाद पिछले बंद भाव के मुकाबले 23 पैसे की गिरावट के साथ 92.85 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा था। रुपये ने शुक्रवार को लगातार पांचवें सत्र में बढ़त जारी रखी थी और यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 70 पैसे मजबूत होकर 92.62 पर बंद हुआ था। रुपया 10 अप्रैल के बाद पहली बार 93 के स्तर से ऊपर पहुंचा था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.03 प्रतिशत गिरकर 103.71 पर रहा।

सोने की कीमत 1,38,460 प्र ति 10 ग्राम तक पहुंचने का अनुमान

केंद्रीय बैंकों की खरीदारी देगी सहारा, ब्याज दरें बनेंगी चुनौती

नई दिल्ली ।

वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सक्स ने 2027 के अंत तक सोने की कीमत 4,650 डॉलर प्रति औंस (लगभग 1,38,460 रुपए) तक पहुंचने का नया अनुमान जारी किया है। यह उनके पिछले 4,800 डॉलर के अनुमान से कम है, फिर भी निवेशकों के लिए सोने की चमक बरकरार रहने की उम्मीद है। 20 नवंबर को सोना 1,23,893 रुपए पर बंद हुआ था। बैंक का अनुमान है कि 2027 के अंत तक सोना 4,650 रुपए प्रति औंस तक पहुंचेगा। इसकी कीमतों को केंद्रीय बैंकों, खासकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा लगातार की जा रही खरीदारी से मुख्य सहारा मिल रहा है। पश्चिमी देशों द्वारा रूस के भंडार फ्रीज होने के बाद यह रुझान बढ़ा है, जिससे अन्य देशों को भी अपनी संपत्ति रखने के तरीकों पर पुनर्विचार करना पड़ा। गोल्डमैन को उम्मीद है कि 2026-28 के दौरान केंद्रीय बैंक प्रति माह औसतन 60 टन सोना खरीदेंगे, जो पहले के 17 टन प्रे तिमाह से काफी अधिक है। हालांकि, अमेरिकी मौद्रिक नीति और ऊंची ब्याज दरें सोने के लिए जोखिम खड़ी कर सकती हैं। गोल्डमैन का मानना है कि फेडरल रिजर्व की संभावित दर वृद्धि से निजी निवेशकों की सोने में रुचि घटेगी, क्योंकि इस पर ब्याज नहीं मिलता।

सेबी का एमआईआई प्रमुखों के कार्यकाल की सीमा तय करने का प्रस्ताव

एमडी के लिए एक संस्थान में 8, कुल 12 साल की सीमा, मौजूदा अधिकारियों को 15 साल तक की छूट

नई दिल्ली ।

बाजार नियामक सेबी ने देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरी कंपनियों जैसे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (एमआईआई) के शीर्ष अधिकारियों के कार्यकाल को लेकर बड़ा प्रस्ताव रखा है। इसके तहत, मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (ईडी) के कार्यकाल की अधिकतम सीमा तय की जाएगी। प्रस्ताव के मुताबिक किसी एक एमआईआई में एमडी का अधिकतम कार्यकाल 8 साल होगा, जबकि अलग-अलग संस्थानों में एमडी के तौर पर काम करने की कुल सीमा 12 साल तय की गई है। हालांकि, पहले से इस पद पर काम कर रहे अधिकारियों को कुल 15 साल तक की छूट मिलेगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए एक संस्थान में 8 साल और कुल 16 साल की सीमा प्रस्तावित है। वर्तमान में एमडी और ईडी एक संस्थान में अधिकतम 10 साल तक काम कर सकते हैं। इस प्रस्ताव का सीधा असर एनएसई और बीएसई जैसे प्रमुख संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों पर पड़ सकता है। एनएसई के एमडी और सीईओ आशीषकुमार चौहान पहले ही विभिन्न एक्सचेंजों में करीब 14 साल इस पद पर रह चुके हैं। उनका मौजूदा कार्यकाल जुलाई 2027 में समाप्त होगा। यदि यह



प्रस्ताव लागू होता है, तो मौजूदा अधिकारियों के लिए प्रस्तावित 15 साल की कुल सीमा उनके भविष्य के कार्यकाल के लिए अहम होगी। बीएसई में भी नए सीईओ की तलाश जारी है, क्योंकि मौजूदा एमडी और सीईओ सुंदररमन राममूर्ति का कार्यकाल जून 2027 में खत्म हो रहा है। यह बदलाव सीडीएसएल और एमसीएक्स जैसे अन्य एमआईआई को भी प्रभावित करेगा।

टाटा स्टील अपने दो कारोबार एपीएल अपोलो ट्यूब्स को 28,000 करोड़ में बेचेगी

एपीएल अपोलो को नए क्षेत्रों में प्रवेश का एक बड़ा अवसर मिलेगा

नई दिल्ली ।

स्टील सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर में दिग्गज कंपनी टाटा स्टील ने अपने दो प्रमुख कारोबारों को एपीएल अपोलो ट्यूब्स को 28,000 करोड़ रुपए के एक बड़े सौदे में बेचने की घोषणा की है। कंपनी बोर्ड ने हाल ही में इस रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दी है, जिसके तहत ट्यूब्स कारोबार और कलर कोटेड स्टील से जुड़ी सहायक कंपनी टाटा स्टील कलर्स की पूरी हिस्सेदारी एपीएल अपोलो को हस्तांतरित की जाएगी। यह सौदा टाटा स्टील के लिए अपने कारोबार को व्यवस्थित करने और निवेश का मूल्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होगा, जबकि एपीएल अपोलो के लिए यह विस्तार का बड़ा अवसर है। इस सौदे के तहत, टाटा स्टील अपने ट्यूब्स कारोबार को अधिकतम 11,700 करोड़ रुपए में बेचेगी, जिसमें स्टील ट्यूब्स, पाइप बनाने, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और बिक्री से जुड़े कार्य शामिल हैं। जमशेदपुर, होसुर, खोपोली और साहिबाबाद की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां भी इस दायरे में आएंगी। दूसरा बड़ा सौदा 16,300 करोड़ रुपए का है, जिसमें टाटा स्टील अपनी सहायक कंपनी टाटा स्टील कलर्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में टाटा ब्लूस्कोप स्टील) की पूरी हिस्सेदारी एपीएल अपोलो को बेचेगी।

इस तरह कुल सौदा 28,000 करोड़ रुपए का है। टाटा स्टील के मुताबिक, इस कदम का मुख्य उद्देश्य अपने डाउनस्ट्रीम कारोबार को व्यवस्थित करना और उसमें किए गए निवेश का मूल्य प्राप्त करना है।

वहीं, एपीएल अपोलो के लिए यह अपने कारोबार के विस्तार और नए क्षेत्रों में प्रवेश का एक बड़ा अवसर होगा, खासकर ट्यूब्स कारोबार को एपीएल अपोलो के बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का लाभ मिलेगा। यह पूरी प्रक्रिया 31 मार्च 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है, हालांकि इसके लिए आवश्यक नियामक मंजूरियां लेना बाकी है। इस बड़े अधिग्रहण के बाद दोनों कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी।

नवंबर में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 9 महीने के उच्च स्तर पर

मुंबई ।

भारत के घरेलू निजी क्षेत्र की कारोबारी गतिविधियों में नवंबर महीने में मामूली तेजी दर्ज की गई। एचएसबीसी के आंकड़ों के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने मजबूत प्रदर्शन किया और इसमें नौ महीने की सबसे तेज बढ़ोतरी देखी गई, जबकि सर्विस सेक्टर की ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ गई। कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) अक्टूबर के 56.2 से बढ़कर नवंबर में 56.3 पर पहुंच गया, जो समग्र आर्थिक सेहत में सुधार का संकेत देता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत रहा, इसका पीएमआई अक्टूबर के 54.7 से बढ़कर नवंबर में 56.0 पर पहुंच गया, जो नौ महीनों का उच्चतम स्तर है। उत्पादन और नए ऑर्डर ने इस क्षेत्र को गति दी। इसके विपरीत, सर्विस सेक्टर का बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स अक्टूबर के 55.8 से घटकर नवंबर में 55.3 पर आ गया, जिससे इसकी रफ्तार में कमी आई। नवंबर में कंपनियों को नए ऑर्डर मिलने की रफ्तार तेज हुई, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में। निर्यात ऑर्डर भी चार महीनों में सबसे तेजी से बढ़े। रोजगार में कुल मामूली बढ़ोतरी हुई। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने सात महीनों में सबसे तेजी से नियुक्तियां कीं, हालांकि, सर्विस सेक्टर में करीब एक साल बाद पहली बार कर्मचारियों की संख्या घटी।

दो बड़े आईपीओ के बीच बिटकॉइन में 23% की गिरावट

क्रिप्टो बाजार से निवेशकों की दूरी

टेक शेयरों की ओर बढ़ रहा निवेश

नईदिल्ली ।

दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन में पिछले एक महीने के दौरान करीब 23 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। दो बड़ी कंपनियों एंथ्रोपिक और स्पेसएक्स के आईपीओ की तैयारियों के बीच क्रिप्टो बाजार में यह गिरावट चर्चा का विषय बनी हुई है। बाजार के जानकारों के मुताबिक, निवेशक क्रिप्टोकरेंसी से पैसा निकालकर टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों में निवेश कर रहे हैं। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, एंथ्रोपिक की 19 नवंबर को प्रस्तावित लिस्टिंग से पहले एक महीने में बिटकॉइन की कीमत 22.7 फीसदी तक गिर गई। इससे पहले स्पेसएक्स की लिस्टिंग से पहले भी एक महीने में बिटकॉइन में 22.3 फीसदी की गिरावट आई थी। इथेरियम भी इस दौरान दबाव में रहा। इसी तरह इथेरियम में भी एंथ्रोपिक के आईपीओ से पहले 25.3 फीसदी और स्पेसएक्स की लिस्टिंग से पहले 28 फीसदी की गिरावट आई थी। बाजार के विशेषज्ञों का मानना है, इसके पीछे केवल आईपीओ नहीं, बल्कि अमेरिकी बिटकॉइन ईटीएफ से भारी निकासी, मुख्य कारण है। निवेशकों की अनिश्चितता, ब्याज दरें बढ़ने की आशंका और बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग पोजिशन का बंद होना भी इस गिरावट के लिए जिम्मेदार है। अमेरिकी बिटकॉइन ईटीएफ से नवंबर में करीब 3.5 अरब डॉलर की निकासी हुई है। आगे क्या होगा? विशेषज्ञों के मुताबिक, बिटकॉइन के लिए 60 हजार से 62 हजार डॉलर का स्तर बेहद महत्वपूर्ण है।

दो का शेयर बना 368! क्यूपिड ने निवेशकों को बनाया करोड़पति

पांच साल में 17,000 फीसदी से ज्यादा का बंपर रिटर्न

नई दिल्ली ।

भारतीय शेयर बाजार में किस्मत पलटने वाले शेयरों की कमी नहीं, क्यूपिड लिमिटेड उनमें से एक है। कंडोम और हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली इस कंपनी के शेयर ने अपने निवेशकों को अप्रत्याशित रूप से मालामाल कर दिया है, एक समय महज 2 रुपये में मिलने वाला यह स्टॉक अब 368 रुपये के पार पहुंच गया है। क्यूपिड लिमिटेड का शेयर पिछले पांच सालों में मल्टीबैगर साबित हुआ है।

26 नवंबर 2021 को जहां इसकी कीमत मात्र 2.13 रुपये थी, वहीं अब यह 368 रुपये के स्तर को छू चुका है। इस दौरान इसने अपने निवेशकों को 17,059.62 फीसदी का अविश्वसनीय रिटर्न दिया है। यदि उस समय किसी निवेशक ने 1 लाख रुपये लगाए होते, तो आज उसकी यह रकम बढ़कर 1.71 करोड़ रुपये से भी अधिक होती। इस तूफानी उछाल से कंपनी का मार्केट कैप भी 49,160 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

यह स्टॉक केवल लंबी अवधि के लिए ही नहीं, बल्कि कम समय में भी निवेशकों को बड़ा मुनाफा दिया है।

पिछले एक साल में शेयर ने 441 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न देकर पैसा पांच गुना किया है। वहीं, छह महीने में ही इसमें 203 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों की रकम लगभग तीन गुनी हो गई।

एफएसएसएआई की कार्रवाई के बाद बिसलेरी ने अपना पानी सुर क्षित बताया

कंपनी ने कहा, मामला पुराना, बाद की जांच में ब्रोमेट सीमा के भीतर

नई दिल्ली ।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मुकदमा चलाने के आदेश के बाद, बिसलेरी इंटरनेशनल ने सोमवार को अपने पैक्ड पेयजल को सुरक्षित बताया है। यह प्रतिक्रिया एफएसएसएआई के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उसने एक नमूने को असुरक्षित बताकर कंपनी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। बिसलेरी ने कहा कि उसे एफएसएसएआई से कोई औपचारिक नोटिस नहीं मिला है और वह नियामक के साथ सहयोग करेगी। बिसलेरी इंटरनेशनल ने स्पष्ट किया कि यह मामला लगभग 14 महीने पुराना है और सितंबर 2025 में उसके गोवा स्थित एक संयंत्र से तैयार बैच से जुड़ा है। एफएसएसएआई ने गोवा संयंत्र से छह नमूने लिए थे, जिनमें से एक में ब्रोमेट का स्तर निर्धारित सीमा (10



माइक्रोग्राम प्रति लीटर) से अधिक (12 माइक्रोग्राम) पाया गया था। हालांकि, कंपनी की अपील पर एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त एक रेफरल प्रयोगशाला ने उसी नमूने की दोबारा जांच की, जिसमें ब्रोमेट की मात्रा तय सीमा के भीतर पाई गई। नतीजों में अंतर आने के बाद, बिसलेरी ने स्वतंत्र रूप से भी जांच कराई, जिसमें भी ब्रोमेट का स्तर स्वीकार्य सीमा के भीतर निकला। कंपनी ने 2 फरवरी, 2026 को इन स्वतंत्र जांच रिपोर्टों को एफएसएसएआई को सौंप दिया था और तब से उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।

त्योहारी सत्र में वाहनों की खुदरा बिक्री रिकॉर्ड 55.25 लाख इकाई पहुंची

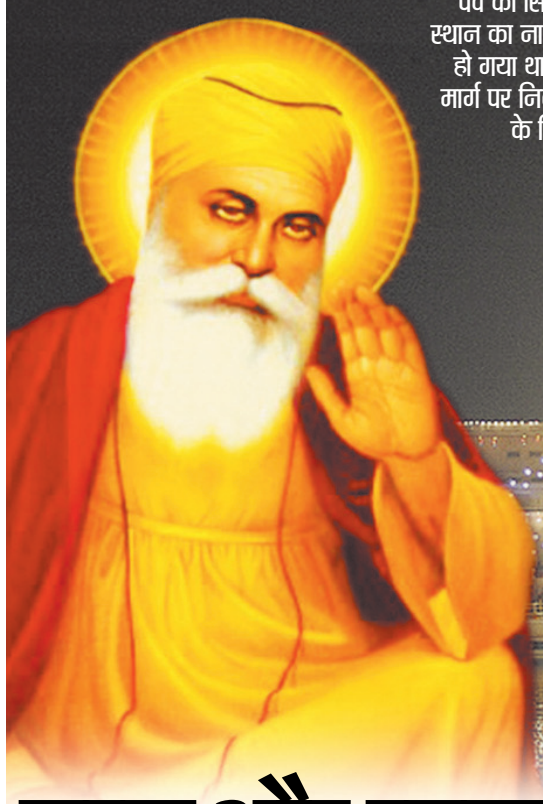
वर्ष 2024 के त्योहारी सत्र की तुलना में खुदरा बिक्री में 23.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई

नई दिल्ली ।

भारत में वाहनों की खुदरा बिक्री इस साल त्योहारी सत्र के दौरान सालाना आधार पर 2.21 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 55.25 लाख इकाई पर पहुंच गई। पिछले साल जीएसटी 2.0 के कारण मांग बढ़ने से ऊंचे आधार के बावजूद यह वृद्धि दर्ज की गई। वाहन डीलरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) ने सोमवार को यह जानकारी दी। फाडा के अनुसार 2026 में 42 दिन की त्योहारी अवधि के दौरान वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 55,25,490 इकाई रही, जो समान अवधि के लिए अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वर्ष 2024 के त्योहारी सत्र की तुलना में वाहनों की खुदरा बिक्री में 23.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाए जाने के बाद मांग की निरंतर रफ्तार को दर्शाती है। दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री सालाना आधार 3.67 प्रतिशत बढ़कर 43,13,276 इकाई हो गई, जबकि तिपहिया वाहनों की बिक्री 5.32 प्रतिशत बढ़कर 1,93,576 इकाई रही। वाणिज्यिक वाहनों की खुदरा बिक्री 7.13 प्रतिशत बढ़कर 1,55,761 इकाई, ट्रैक्टर की बिक्री 2.24 प्रतिशत बढ़कर 1,03,809 इकाई और निर्माण उपकरणों की बिक्री 26.06 प्रतिशत उछलकर 10,452 इकाई पर पहुंच गई।

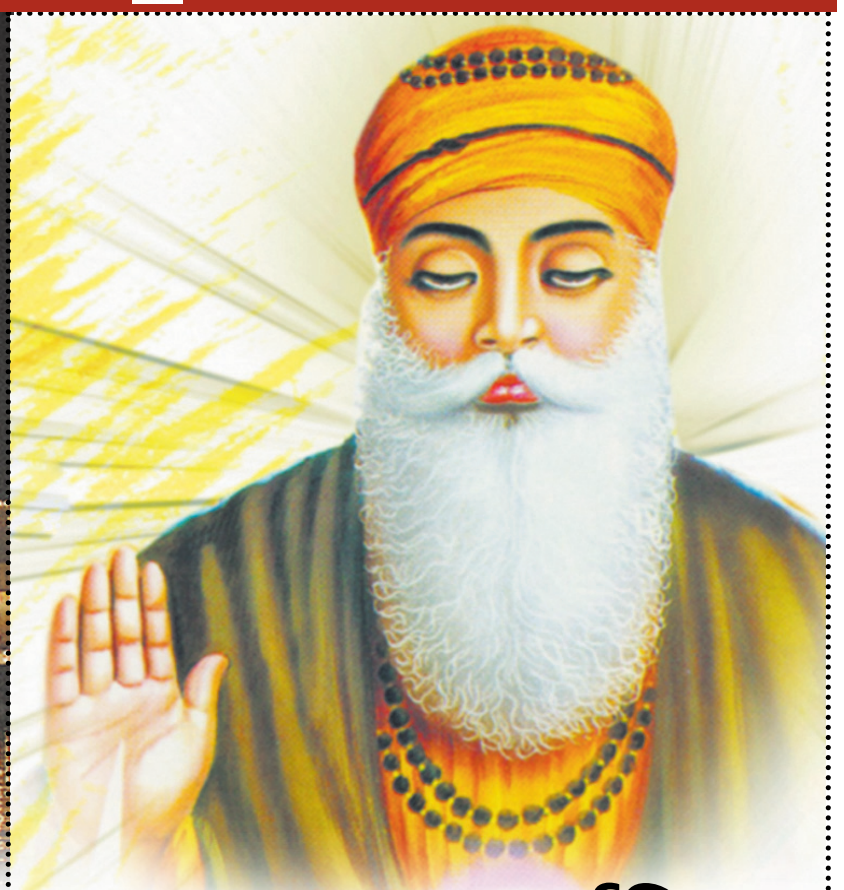
हालांकि, यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 7.16 प्रतिशत घटकर 7,48,616 इकाई रह गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 8,06,322 इकाई थी। इस दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खुदरा बिक्री 52.62 प्रतिशत उछलकर पांच लाख इकाई के पार निकल गई। इसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों का मुख्य योगदान रहा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1



सिक्ख धर्म के संस्थापक गुरुनानक देवजी के जन्मदिवस को प्रकाश पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है. गुरुनानक जयंती के पर्व को सिक्ख धर्म के लोगों के अलावा अन्य धर्म के लोग भी खासे उत्साह से मनाते हैं. गुरुनानक का जहां जन्म हुआ था, उस स्थान का नाम उनके नाम 'ननकाना' से जाना जाता है. ननकाना अब पाकिस्तान में है. नानकजी का विवाह 16 वर्ष की उम्र में ही हो गया था. नानकदेव का मन धर्म और अध्यात्म की ओर था, इसलिए वो अपनी पत्नी और बच्चों को ससुराल में छोड़कर धर्म के मार्ग पर निकल गए. गुरुनानकजी ने अपने पूरे जीवन में सामाजिक कुरीतियों का पुरजोर विरोध किया. समाज में एकरूपता लाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया. ऐसा माना जाता है कि गुरुनानक देव ने 1539 में देह का त्याग किया.





सरल और स्पष्ट है
गुरुनानक देवजी का व्यक्तित्व

गुरु नानक देवजी सिख धर्म के संस्थापक ही नहीं, अपितु मानव धर्म के उत्थापक थे। वे केवल किसी धर्म विशेष के गुरु नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि के जगद्गुरु थे। 'नानक शाह फकीर। हिन्दू का गुरु, मुसलमान का पीर। उनका जन्म पूर्व भारत की पावन धरती पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 को लाहौर से करीब 40 मील दूर स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कल्याणराय मेहता तथा माता का नाम तृपताजी था।

भाई गुरुदासजी लिखते हैं कि इस संसार के प्राणियों की त्राहि-त्राहि को सुनकर अकाल पुरख परमेश्वर ने इस धरती पर गुरु नानक को पहुंचाया, 'सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग महि पठाइया।' उनके इस धरती पर आने पर 'सतिगुरु नानक प्रगटिआ मिटी धुंधू जगि चानणु होआ' सत्य है, नानक का जन्मस्थल अलौकिक ज्योति से भर उठा था। उनके मस्तक के पास तेज आभा फैली हुई थी। पुरोहित पंडित हरदयाल ने जब उनके दर्शन किए उसी क्षण भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बालक ईश्वर ज्योति का साक्षात अलौकिक स्वरूप है। बचपन से ही गुरु नानक का मन आध्यात्मिक ज्ञान एवं लोक कल्याण के चिंतन में डूबा रहता। बैठे-बैठे ध्यान मग्न हो जाते और कभी तो यह अवस्था समाधि तक भी पहुंच जाती। गुरु नानक देवजी का जीवन एवं धर्म दर्शन युगांतकारी लोकचिंतन दर्शन था। उन्होंने सांसारिक यथार्थ से नाता नहीं तोड़ा। वे संसार के त्याग संन्यास लेने के खिलाफ थे, क्योंकि वे सहज योग के हामी थे। उनका मत था कि मनुष्य संन्यास लेकर स्वयं का अथवा लोक कल्याण नहीं कर सकता, जितना कि स्वाभाविक एवं सहज जीवन में।

इसलिए उन्होंने गृहस्थ त्याग गुफाओं, जंगलों में बैठने से प्रभु प्राप्ति नहीं अपितु गृहस्थ में रहकर मानव सेवा करना श्रेष्ठ धर्म बताया। 'नाम जपना, किरत करना, वंड छकना' सफल गृहस्थ जीवन का मंत्र दिया। यही गुरु मंत्र सिख धर्म की मुख्य आधारशिला है। यानी अंतर आत्मा से ईश्वर का नाम जपो, ईमानदारी एवं परिश्रम से कर्म करो तथा अर्जित धन



से असहाय, दु:खी पीड़ित, जरूरततमंद इंसानों की सेवा करो।

गुरु उपदेश है, 'घाल खाये किछ हत्थो देह। नानक राह पछाने से।' इस प्रकार श्री गुरुनानक देवजी ने अन्न की शुद्धता, पवित्रता और सात्विकता पर जोर दिया। गुरु नानक देव एक मर्तबा एक गांव में पहुंचे तो उनके लिए दो घरों से भोजन का निमंत्रण आया। एक निमंत्रण गांव के धनाढ्य मुखिया का था, दूसरा निर्धन बढ़ई का था। नानक जी ने मुखिया के घी से बने मिष्ठान को ग्रहण न करके बढ़ई किसान की रूखी रोटियां को सप्रेम स्वीकार किया। इस पर मुखिया ने अपना अपमान समझा। गुरुजी ने मुखिया की रोटियों को निचोड़ा तो उसमें से रक्त टपका। दूसरी ओर किसान की रोटियों को निचोड़ा तो उसमें से निर्मल दूध की धारा फूट पड़ी।

गुरुनानक देवजी ने कहा कि मुखिया की कमाई, जो अनीति, अधर्म, अत्याचार, शोषण से प्राप्त की कमाई है जबकि काश्तकार ने यह अन्न ईमानदारी, मेहनत से प्राप्त किया है। इसमें लेशमात्र भी अनीति, अन्याय, शोषण, मलिनता नहीं है। कु-अन्न के प्रभाव से मन मलिन, प्रदूषित तथा विकारों से युक्त हो जाता है। ऐसा भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, वह ग्राह्य नहीं है। शुद्ध, सात्विक, नीति-धर्म का पालन करते हुए प्राप्त किया हो, वह आहार मानव मन को विकार रहित, निर्मल, पवित्र और सात्विक बनाता है। इसी प्रकार ईश्वरीभाव एवं भय के साथ पूरी ईमानदारी के साथ कर्म करने की बात भी गुरुजी ने कही।

गुरुनानक देवजी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व जितना सरल, सीधा और स्पष्ट है, उसका अध्ययन और अनुसरण भी उतना ही व्यावहारिक है। गुरु नानक वाणी, जन्म साखियों, फारसी साहित्य एवं अन्य ग्रंथों के अध्ययन से यह सिद्ध होता है। गुरुनानक ने सभी धर्मों को श्रेष्ठ बताया। जरूरत है धर्म के सत्य ज्ञान को आत्मसात कर अपने व्यावहारिक जीवन में लाने की। गुरुजी ने धार्मिक एवं सामाजिक विषमताओं पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने वाणी में हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए एकात्मकता के बीज बोए। उनका मत था कि संपूर्ण सृष्टि का ईश्वर एक है। हम सब तो उसके बंदे हैं- 'एक पिता एकस के बारिक'। हमारा धर्म एक है। गुरुजी स्वयं एकेश्वर में पूर्ण विश्वास रखते थे। उनका दृष्टिकोण समन्वयवादी था।

वे कहते हैं- 'सबको ऊंचा आखिए/ नीच न दिसै कोई।' गुरुजी ने ऐसे मनुष्यों को प्रताड़ित किया है, जिनके मन में जातीय भेदभाव है और कहा कि वह मनुष्य नहीं, पशु के समान है- जीनके भीतर हैं अंतरा जैसे पशु तेसे वो नरा'। ऊंच-नीच के भेदभाव मिटाने के लिए गुरुजी ने कहा कि मैं स्वयं भी ऊंची जाति कहलाने वालों के साथ नहीं बल्कि मैं जिन्हें नीची जात कहा जाता है, उनके साथ हूँ। 'नीचा अंदरि नीच जाति, नीचिंहु अति नीचु/ नानक तिन के संग साथ, वडिया सिऊ किया रीस। गुरुनानक देवजी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व जितना सरल, सीधा और स्पष्ट है, उसका अध्ययन और अनुसरण भी उतना ही व्यावहारिक है। गुरु नानक वाणी, जन्म साखियों, फारसी साहित्य एवं अन्य ग्रंथों के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि गुरुनानक उदार प्रवृत्ति वाले स्वतंत्र और मौलिक चिंतक थे। एक सामान्य व्यक्ति और एक महान आध्यात्मिक चिंतक का एक अद्भुत मिश्रण गुरु नानकदेवजी के व्यक्तित्व में अनुभव किया जा सकता है। 'वे नबी भी थे और लोकनायक भी, वे साधक भी थे और उपदेशक भी, वे शायर एवं कवि भी थे और ढाढ़ी भी, वे गृहस्थी भी थे और पर्यटक भी।'

मानवता का संदेश देता है प्रकाश पर्व

कार्तिक मास की पूर्णिमा पर सिक्ख धर्मावलंबियों द्वारा प्रकाश पर्व मनाया जाता है। प्रकाश पर्व सिक्ख धर्म के संस्थापक गुरुनानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार गुरुनानक देव परिवार कृषि आदि कार्य से संबंधित था। गुरुनानक का जहां जन्म हुआ था वह स्थान उन्हीं के नाम पर अब ननकाना के नाम से जाना जाता है। ननकाना अब पाकिस्तान में है। नानकदेवजी बचपन से प्रखर बुद्धि थे। प्रारंभ से ही इनके चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई देता था। नानकजी का विवाह 16 वर्ष की उम्र में हुआ। इनके दो पुत्र हुए। चूंकि नानकदेव का मन धर्म और अध्यात्म की ओर था अत- वे पत्नी और बच्चों को ससुराल में छोड़कर धर्म के मार्ग पर निकल गए। गुरुनानकजी ने अपने पूरे जीवन में सामाजिक कुरीतियों का पुरजोर विरोध किया। समाज में एकरूपता लाने के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। इन्होंने यही संदेश दिया कि ईश्वर एक है और हमें उसी की आराधना करनी चाहिए। गुरुनानकजी ने भारत सहित अनेक देशों की यात्राएं की। वे मानवीय और धार्मिक एकता के उपदेशों और शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि गुरुनानक देव ने 1539 देह का त्याग किया।

प्रकाश पर्व और नगर कीर्तन का महत्व



सिखों के पहले गुरु नानकदेवजी की जयंती देशभर में प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। प्रकाश पर्व यानी मन की बुराइयों को दूर कर उसे सत्य, ईमानदारी और सेवाभाव से प्रकाशित करना। सिखों के प्रथम गुरु, गुरु नानकदेवजी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में विशाल नगर कीर्तन निकाला जाता है। इस दौरान पंज (पांच) प्यारे नगर कीर्तन की अगुवाई करते हैं। श्री गुरुग्रंथ साहिब को फूलों की पालकी से सजे वाहन पर सुशोभित करके कीर्तन विभिन्न जगहों से होता हुआ गुरुद्वारे पहुंचता है। प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में प्रभातफेरी निकाली जाती है जिसमें भारी संख्या में संगतें भाग लेती हैं। प्रभातफेरी के दौरान कीर्तनी जत्थे कीर्तन कर संगत को निहाल करते हैं। इस अवसर पर गुरुद्वारे के सेवादार संगत को गुरु नानकदेवजी के बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कहते हैं कि श्री गुरु नानकदेव महाराज महान युगपुरुष थे। नानकदेवजी ने अपना पूरा जीवन समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में समर्पित कर दिया। ऐसे महान युगपुरुष की आज के समय में बहुत जरूरत है। भगवान एक है। एक ही गुरु है और कोई नहीं। जहां गुरु जाते हैं, वह स्थान पवित्र हो जाता है। भगवान को याद करने, मेहनत से कमाई करने और उसके बाद बांट के खाने का संदेश दुनियाभर में देने वाले ऐसे ही गुरु को सिख समुदाय उनकी जयंती पर याद करता है। एक ओर जहां गुरुद्वारों में भव्य सजावट की जाती है, वहीं गुरु का प्रसाद लंगर भी बांटा जाता है। साथ ही गुरु नानकदेवजी पर आधारित पोस्टर जारी किए जाते हैं। अपनी परंपरानुसार प्रभातफेरी में शामिल स्त्री-पुरुष सफेद वस्त्र एवं केसरिया चुन्नी धारण कर गुरुवाणी का गायन करते हुए चलते हैं। > सभी जत्थों का जगह-जगह पर हार-फूल से स्वागत किया जाता है। शाम को दीवान सजाकर शबद कीर्तन का कार्यक्रम भी किया जाता है। यह पर्व समाज के हर व्यक्ति को साथ में रहने, खाने और मेहनत से कमाई करने का संदेश देता है। गुरु नानकदेवजी का प्रकाश पर्व सिख समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है।

जब गुरु नानक के आगे झुका बगदाद के शासक का सिर

एक बार गुरु नानक बगदाद गए हुए थे। वहां का शासक बड़ा ही अत्याचारी था। वह जनता को कष्ट तो देता ही था, उनकी संपत्ति लूटकर अपने खजाने में जमा भी कर लिया करता था। उसे जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान से कोई साधु पुरुष आया है तो वह नानकजी से मिलने उनके पास पहुंचा। कुशल समाचार पूछने के उपरांत नानकजी ने उससे 100 पत्थर गिरवी रखने की विनती की।

शासक बोला, 'पत्थर गिरवी रखने में कोई आपत्ति नहीं है किंतु आप उन्हें ले कब जाएंगें?'

'आपके पूर्व ही मेरी मृत्यु होगी। मेरे मरणोपरांत, इस संसार में आपकी जीवन यात्रा समाप्त होने पर जब आप मुझसे मिलेंगे, तब इन पत्थरों को मुझे दे दीजिएगा,' नानक बोले।

'आप भी कैसी बातें करते हैं, महाराज। भला इन पत्थरों को लेकर मैं वहां कैसे जा सकता हूं?'

'तो फिर जनता को चूस-चूसकर आप जो अपने खजाने में नित्य वृद्धि किए जा रहे हैं, क्या वह सब यहीं छोडेंगे? उसे भी अपने साथ ले ही जाएंगे। बस साथ में मेरे इन पत्थरों को भी लेते आइएगा।'

इतना सुनते ही उस दुराचारी की आंखें खुल गईं। नानक के चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगा।

नानक ने कहा, 'मुझसे क्षमा क्यों मांगते हो और मैं कौन होता हूं क्षमा करने वाला। वैसे भी तुमने मुझे को कोई कष्ट दिया नहीं कि तुम मुझसे क्षमा मांगो। अगर क्षमा मांगनी ही है तो अपने देश की जनता से मांगो जिसका तुमने खून चूसा है। तुम यदि समझ रहे हो कि तुमने गलत किया है तो वचन दो कि आज के बाद कभी अपनी प्रजा को कष्ट नहीं दोगे।'

शासक की समझ में सारी बात आ गई। उसने नानकजी को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेगा। नानकजी ने उसे क्षमा कर दिया और वह शासक प्रजा को कष्ट न देने के वचन के साथ अपने महल की ओर चल दिया।



महान दार्शनिक गुरु नानक देव

गुरुनानक देव के चेहरे पर बाल्यकाल से ही अद्भुत तेज दिखाई देता था। उनका जन्म लाहौर के पास तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। उनका परिवार कृषि करके आमदनी करते थे। गुरुनानक का जहां जन्म हुआ था वह स्थान आज उन्हीं के नाम पर अब ननकाना के नाम से जाना जाता है। ननकाना अब पाकिस्तान में है। बचपन से प्रखर बुद्धिवाले नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं। वे उम्र के 16वें वर्ष में शादी होने के बाद अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को छोड़कर धर्म के मार्ग पर निकल पड़ें। बचपन से ही उनका मन धर्म और अध्यात्म में लगता था। कहा जाता है कि गुरुनानक देव ने एक ऐसे विकट समय में जन्म लिया जब भारत में कोई केंद्रीय संगठित शक्ति नहीं थी। विदेशी आक्रमणकारी भारत देश को लूटने में लगे थे। धर्म के नाम पर अंधविश्वास और कर्मकांड चारों तरफ फैले हुए थे। ऐसे समय में नानक एक महान दार्शनिक, विचारक साबित हुए। उन्होंने अपनी सुमधुर सरल वाणी से जनमानस के हृदय को जीत लिया। लोगों को बेहद सरल भाषा में समझाया सभी इंसान एक दूसरे के भाई है। ईश्वर सबके पिता है, फिर एक पिता की संतान होने के बावजूद हम ऊंच-नीच कैसे हो सकते है? इन्हीं सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए उन्होंने उपदेशों को अपने जीवन में अमल किया और चारों ओर धर्म का प्रचार कर स्वयं एक आदर्श बने। सामाजिक सद्भाव की मिसाल कायम की। ऊंच-नीच का भेदभाव मिटाने के लिए लंगर की परंपरा चलाई। जहां कथित अछूत और उच्च जाति के लोग एक साथ लंगर में बैठकर एक पंक्ति में भोजन करते थे। आज भी सभी गुरुद्वारों में यही लंगर परंपरा कायम है। लंगर में बिना किसी भेदभाव के संगत सेवा करती है। गुरु नानक देव ने भारत सहित अनेक देशों की यात्राएं कर धार्मिक एकता के उपदेशों और शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार कर दुनिया को जीवन का नया मार्ग बताया। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर गुरु नानक जयंती मनाई जाती है।

कार्तिक पूर्णिमा को किए दान का मिलता है अक्षय फल



एक वर्ष पंद्रह पूर्णिमाएं होती हैं। जब अधिकमास या मलमास आता है, तो 16 पूर्णिमा मनाई जाती हैं। इस महीने की चार तारीख यानी चार नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, सिखों के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसे त्रिपुरी पूर्णिमा, महाकार्तिकी या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। सृष्टि के आरंभ से ही कार्तिक पूर्णिमा की तिथि खास रही है। स्कंद पुराण, नारद पुराण पद्म पुराण आदि में इस दिन स्नान,व्रत व तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। इसका महत्व सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं शैव भक्तों और सिख धर्म के लिए भी अधिक है।

वैष्णव भक्तों के लिए इसलिए है खास

विष्णु के भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में थे। भगवान को यह अवतार वेदों की रक्षा,प्रलय के अंत तक सप्तऋषियों,अनाजों एवं राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था। इससे सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से आसान हुआ।

इस दिन शिव बने थे त्रिपुरारी

शिव भक्तों के अनुसार इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार कर दिया जिससे वह त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए। इससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया जो शिव के अनेक नामों में से एक है। इसलिए इसे 'त्रिपुरी पूर्णिमा' भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा जब आकाश में उदित हो रहा हो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा इन छह कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की कृपा बनी रहती है।

सिखों के लिए इस दिन का महत्व

कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि इसी दिन सिख सम्प्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन सिख सम्प्रदाय के अनुयाई सुबह स्नान कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए रास्ते पर चलने की सौगंध लेते हैं। इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

ड्रग कार्टेल का सरगना एल चापो इसिद्रो गिरफ्तार, सड़कों पर गिरोह के लोगों ने की गोलीबारी; 11 की मौत

सिनालोआ, एजेंसी। मैक्सिको के सिनालोआ राज्य में ड्रग कार्टेल के एक बड़े सरगना की गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़क उठी। शुक्रवार रात शुरू हुई गोलीबारी और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। मैक्सिको के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, मारे गए लोगों में कार्टेल के सात संदिग्ध बंदूकधारी और चार सैनिक शामिल हैं। कार्टेल सरगना फॉस्तो इसिद्रो मेजा फ्लोरेस को 'एल चापो इसिद्रो' के नाम से जाना जाता है। वह एफबीआई की दस सर्वाधिक वांछित भगोड़ों की सूची में शामिल था। अमेरिकी खुफिया जानकारी के आधार पर मैक्सिको के अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार किया। इस अभियान में मेजा फ्लोरेस समेत आठ लोगों को हिरासत में लिया गया। मेजा फ्लोरेस बेल्ट्रान लेवा कार्टेल में ऊंचे पद तक पहुंचा था। बाद में उसने अपना अलग संगठन मेजा-फ्लोरेस ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन बनाया। अमेरिका ने उसकी गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी देने पर पांच मिलियन डॉलर के इनाम की घोषणा कर रखी थी। उस पर अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप थे।

फ्रांस में न्यूज चैनलों के खिलाफ गुस्सा दक्षिणपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप, चैनल बंद करने की मांग

पेरिस, एजेंसी। फ्रांस के प्रमुख न्यूज चैनल बीएफएम टीवी के न्यूजरूम में इन दिनों अजीब-सी बेचैनी का माहौल है। तकनीशियन थॉमस लियोनेटी और उनके 159 साथियों ने अपने ही प्रबंधन के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। प्रबंधन को लिखे एक पत्र में इन कर्मचारियों ने कहा है कि चैनल पर जिस तरह दक्षिणपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे उन्हें अब बीएफएम टीवी में काम करने पर शर्म महसूस होती है। फ्रांस में पिछले दो महीनों से जारी छात्र आंदोलनों और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच बीएफएफ के अलावा एक अन्य प्रमुख न्यूज सी-न्यूज भी सवालों के घेरे में है। विवाद इस कदर बढ़ चुका है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर कर फ्रांसीसी सरकार से सी-न्यूज का प्रसारण लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। लोगों का आरोप है कि चैनल नस्लवादी भाषा और दक्षिणपंथी दुष्प्रचार के जरिए नफरत फैला रहा है। हालांकि, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने सी-न्यूज का लाइसेंस रद्द करने से इन्कार करते हुए कहा कि यह सांसदों का काम नहीं है, बल्कि इस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहस होगी। 2019 से अब तक फ्रांस के प्रसारण नियामक की ओर से सी-न्यूज को 20 बार चेतावनी या दंड दिया जा चुका है, जिसमें छह बार तो इसी साल कार्रवाई हुई है। जब फ्रांस में विरोध प्रदर्शन भड़के तो इन चैनलों ने जलती कारों, टूटे शीशों और तीखी टिप्पणियों का पुराना फॉर्मूला अपनाया। नतीजा यह हुआ कि जनता का गुस्सा अब खुद इन चैनलों की टीमों पर फूटने लगा है। इसी महीने ल्योन शहर में प्रदर्शन कवर कर रही बीएफएम की कैमरा टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। वहीं, ट्रैप्स उपनगर में शोक सभा के दौरान चैनल की टीम से बदसलूकी की गई।

बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का हमला- पैट्रियट एयर डिफेंस रडार को बनाया निशाना, दी क्या चेतावनी

तेहरान, एजेंसी। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से संयुक्त हमला किया। संगठन के मुताबिक, इस कार्रवाई में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े दो रडार को निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी प्रसारक आईआरआईबी पर प्रसारित बयान के अनुसार, आईआरजीसी की एयरोस्पेस फोर्स ने बहरीन के अल-रिफा और अवाली सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, इन ठिकानों पर अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े रडार तैनात हैं। आईआरजीसी ने कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी एमक्यू-1 और एमक्यू-9 ड्रोन की ओर से ईरानी हवाई क्षेत्र के कथित बार-बार उल्लंघन और ईरान के हेंगम द्वीप पर एक रडार प्रतिष्ठान पर हमले के जवाब में की गई। संगठन ने यह भी दावा किया कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य एस्कॉर्ट और हवाई सुरक्षा अभियान अपने उद्देश्यों को हासिल करने में नाकाम रहे। आईआरजीसी ने ईरान के हवाई क्षेत्र को रेड लाइन बताते हुए चेतावनी दी कि आगे किसी भी तरह की घुसपैठ होने पर कड़ी और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी।

विमान में घुसे नकाबपोश अधिकारी, मां के सामने बेटी को ले गए; उड़ान में देरी, क्यों उठ रहे सवाल

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के सिएटल-टैकोमा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को आव्रजन (इमिग्रेशन) अधिकारियों ने दो यात्रियों को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। उन्होंने यात्रियों के विमान में सवार होने के दौरान यह कार्रवाई की। इससे वहां अफरातफरी मच गई। इस कारण लॉस एंजिलिस जाने वाली उड़ान में देरी हुई। एयरलाइन अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने भी इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई। यह घटना उस समय हुई, जब यात्री अलास्का एयरलाइंस की उड़ान संख्या 1306 में सवार हो रहे थे। इस विमान को सुबह 8:10 बजे रवाना होना था। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में अधिकारी जमीन पर गिरे एक व्यक्ति को काबू करने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान आसपास यात्री अपना सामान लेकर खड़े थे। एक महिला चिल्ला रही थी कि अधिकारी उसकी बेटी को ले जा रहे हैं। उसने यह भी कहा कि उसकी बेटी के पास काम करने का परमिट है। एयरलाइन ने इस घटना को यात्रियों और कर्मचारियों के लिए परेशान करने वाला बताया। उसने कहा कि अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी के अधिकारियों ने इस कार्रवाई से पहले एयरलाइन को कोई जानकारी नहीं दी थी।

अमेरिकी एजेंसी ने क्या वजह बताई : अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी ने एक्स पर एक



बयान जारी किया। उसने बताया कि उसके अधिकारियों ने 21 नवंबर को सुबह करीब 8:05 बजे (स्थानीय समय) एक विशेष अभियान चलाया था। इस अभियान का मकसद रिकार्डो लारोंदो मेंडोजा को गिरफ्तार करना था। वह मेक्सिको का नागरिक है। एजेंसी के मुताबिक, वह अपने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रह रहा था। एजेंसी ने अपने बयान में कहा, 21 नवंबर, 2026 को सुबह करीब 8:05 बजे, एजेंसी के अधिकारियों ने रिकार्डो लारोंदो मेंडोजा को हिरासत में लेने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। वह मेक्सिको का एक अवैध प्रवासी है, जिसने हमारे देश के कानूनों का उल्लंघन करते हुए अपने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी यहां रहना जारी रखा। एजेंसी ने बताया कि इस दौरान एक अन्य यात्री सोफिया हर्नांडेज मेजिया को भी हिरासत में लिया गया। आरोप है कि उसने हंगामे के दौरान अधिकारियों पर गर्म कॉफी फेंकी थी। एजेंसी के मुताबिक, सोफिया मेक्सिको की नागरिक है। वह भी अपने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद अमेरिका में रह रही थी। उस पर एक संघीय अधिकारी पर हमला करने का आरोप लगाया जा सकता है।

अलास्का एयरलाइंस ने कार्रवाई पर क्या कहा : अलास्का एयरलाइंस ने इस कार्रवाई पर चिंता जताई। उसने कहा कि विमान में यात्रियों के सवार होने के दौरान यह कार्रवाई की गई। इससे पहले एयरलाइन को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। एयरलाइन ने एक बयान में कहा, अलास्का की उड़ान संख्या 1306 में यात्रियों के सवार होने के दौरान आज सुबह हुई कानून लागू करने वाली एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर हम चिंतित हैं। एयरलाइन ने आगे कहा, हम इस बात को समझते हैं कि इस घटना से प्रभावित कर्मचारियों और यात्रियों को कितनी परेशानी हुई है। उसने दोहराया कि वह यात्रियों के साथ सम्मान और गरिमा से पेश आने के लिए प्रतिबद्ध है। एयरलाइन ने बताया कि वह सिएटल बंदरगाह प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है। यही प्रशासन सिएटल-टैकोमा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन करता है। दोनों यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस कार्रवाई में तय नियमों का पालन किया गया था। एयरलाइन ने यह भी कहा कि उसने सीधे संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी चिंता रखी है।

जानकारी के मुताबिक, इस घटना के बाद विमान की उड़ान में देरी हुई। वाशिंगटन के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने अधिकारियों की कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने एजेंसी के तरीकों को अमेरिका के मूल्यों के पूरी तरह खिलाफ बताया। साथ ही, उन्होंने इस एजेंसी को खत्म करने की भी मांग की। श्रमिक संगठनों के नेताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्ग्यूसन ने कहा, वीडियो खौफनाक है और इसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, हमें ऐसी आव्रजन व्यवस्था और सीमा सुरक्षा की जरूरत है, जो प्रभावी, नैतिक और मानवीय हो। लेकिन यह एजेंसी ऐसी नहीं है। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। फर्ग्यूसन ने यह भी कहा कि वह इस बात की जांच कर रहे हैं कि संघीय अधिकारियों को विमान में चढ़ने वाले रास्ते तक पहुंच कैसे मिली। उन्होंने आशंका जताई कि अधिकारियों ने मार्च में उनके हस्ताक्षर से बने एक राज्य कानून का उल्लंघन किया हो सकता है। यह कानून कानून लागू करने वाले अधिकारियों के चेहरे ढकने पर रोक लगाता है।

नई सरकार बनाने की कोशिशों को झटका? नेतन्याहू की पार्टी ने रखीं कई शर्तें; क्या मानेंगे विपक्षी नेता

यरुशलम, एजेंसी। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड ने कई शर्तें रखी हैं। ये शर्तें संभावित राष्ट्रीय एकता सरकार में शामिल होने के लिए हैं। पार्टी ने कहा है कि युद्ध के दौरान बनाए गए इस्राइली सुरक्षा क्षेत्र बने रहने चाहिए। ये सुरक्षा क्षेत्र गाजा पट्टी, लेबनान और सीरिया में बनाए गए हैं। लिकुड ने ये मांगें एक आधिकारिक दस्तावेज में रखी हैं। यह दस्तावेज उस समय सामने आया, जब गादी आइजेनकोट की पार्टी याशर ने शनिवार को लिकुड को बातचीत का न्योता दिया। याशर ने राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के लिए गठबंधन की बातचीत शुरू करने को कहा। पार्टी ने इसे लंबी और लगातार चलने वाली बातचीत बताया। याशर ने कहा कि उसकी बातचीत करने वाली टीम हरसंभव रास्ता तलाशेगी। टीम बड़े कदम उठाएगी। वह ऐसा रास्ता खोजेगी, जिससे नई सरकार बनाने की दिशा में सफलता मिल सके। लिकुड की दूसरी शर्तें क्या हैं? लिकुड की प्रस्तावित शर्तों में कई और बातें शामिल हैं। लिकुड की मांग है कि इस्राइल को यहूदी लोगों का राष्ट्र माना जाए। वह फलस्तीनी राष्ट्र बनाने के प्रस्ताव को खारिज करती है। पार्टी यह भी चाहती है कि अति-रूढ़िवादी विचारों को मानने वाले यहूदी छात्रों की सैन्य सेवा को लेकर भी सहमति बने। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने यह जानकारी दी। क्या हमास के हमले की जांच पर भी शर्त रखी गई है? इससे पहले लिकुड ने राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के लिए एक और शर्त रखी थी। यह सरकार गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के साथ बननी है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, लिकुड ने कहा था कि हमास के सात अक्तूबर, 2023 के हमले की जांच के लिए राज्य जांच आयोग नहीं बनाया जाना चाहिए। हमले के बाद से विपक्षी दल ऐसे आयोग की मांग कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू के गठबंधन ने इस मांग को खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि ऐसा आयोग निष्पक्ष नहीं होगा। इस्राइल के सरकारी समाचार चैनल कान के मुताबिक, रविवार को दोनों दलों के नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक में जांच आयोग बनाने की शर्त पर भी चर्चा हो सकती है। शिन्हुआ ने कान न्यूज के हवाले से यह जानकारी दी। लिकुड ने कान न्यूज से कहा कि बातचीत के दौरान अहम विवादों पर चर्चा होनी चाहिए। इनमें हमास के हमले की जांच के लिए आयोग बनाने का मुद्दा भी शामिल है। आइजेनकोट पहले सेना प्रमुख रह चुके हैं। उन्हें सरकार बनाने के लिए छह दिसंबर तक का समय मिला है। राष्ट्रपति उन्हें दो सप्ताह तक का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं। 27 अक्तूबर को हुए चुनाव में नेतन्याहू के विरोधियों को संसद की कुल 120 सीटों में से 67 सीटें मिलीं।

जेलेंस्की की दो टूक, नाटो की सदस्यता ही यूक्रेन की मजबूत सुरक्षा; बोले- दो साल नहीं, हमेशा के लिए चाहिए गारंटी

कीव, एजेंसी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दोहराया है कि देश की सुरक्षा की सबसे स्पष्ट गारंटी नाटो की सदस्यता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के इस सैन्य गठबंधन में शामिल होने से नाटो भी मजबूत होगा। सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में उन्होंने बताया कि बर्लिन में कोएलिशन ऑफ द विलिंग यानी इच्छुक देशों के गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सहयोगी देश भी नाटो सदस्यता को सबसे प्रभावी विकल्प मानते हैं। जेलेंस्की ने नाटो के अनुच्छेद-5 जैसी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी व्यवस्था कैसे काम करेगी। उन्होंने पूछा कि रूस के नए हमले की स्थिति में सहयोगी देश यूक्रेन की रक्षा के लिए कितने तैयार होंगे। उनके मुताबिक, किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था में ठोस सैन्य प्रतिबद्धताएं जरूरी हैं। जेलेंस्की ने कहा कि सुरक्षा गारंटी केवल बयानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इन्हें लिखित रूप में स्पष्ट किया जाना चाहिए, ताकि संकट के समय सहयोगी देशों की जिम्मेदारियां तय रहें। उन्होंने जोर दिया कि यूक्रेन को ऐसी व्यवस्था चाहिए, जो हमले की स्थिति में उसकी रक्षा कर सके। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि सुरक्षा गारंटी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रभावी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमें दो साल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए सुरक्षा गारंटी चाहिए। उनके अनुसार, अस्थायी व्यवस्था से स्थायी शांति सुनिश्चित नहीं हो सकती। जेलेंस्की ने दावा किया कि पुतिन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को बदलने और दुनिया को प्रभाव क्षेत्रों में बांटने के अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए हैं। उन्होंने यूक्रेन पर रातभर में 111 मिसाइलों के हमले की आलोचना करते हुए रूस को निशाने पर लिया। जेलेंस्की ने ओलेशकी से नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद के लिए अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप का आभार जताया।

इमिग्रेशन सुधार पर रिपब्लिकन में रार; वेंस ने केविन स्टिट के द्विदलीय कानून के प्रस्ताव को ठुकराया

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ओक्लाहोमा के गवर्नर केविन स्टिट की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपने कार्यकाल के आखिरी दो वर्षों में आव्रजन (इमिग्रेशन) पर दोनों दलों (रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी) की सहमति से कानून बनाने का आग्रह किया था। वेंस ने चेतावनी दी कि ऐसा करने से उन लोगों को माफी (एमनेस्टी) मिल सकती है, जिन्होंने अमेरिकी आव्रजन नियमों का उल्लंघन किया है। यह मतभेद तब सामने आया, जब रिपब्लिकन पार्टी के ही सदस्य स्टिट ने ट्रंप से आव्रजन कानूनों पर डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करने को कहा। उनका तर्क था कि वाशिंगटन में दोनों दलों के बीच गतिरोध के कारण इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। 19 नवंबर को जवाब देते हुए वेंस



ने वीजा धोखाधड़ी और नियोक्ताओं द्वारा नियमों के उल्लंघन को रोकने के प्रयासों को उन प्रस्तावों से अलग बताया, जिनमें बिना वैध दस्तावेजों वाले प्रवासियों को कानूनी दर्जा देने की बात कही जाती है।

बड़ी कंपनियों और नियोक्ताओं पर सख्ती के पक्ष में वेंस : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए वेंस ने कहा कि वह ऐसी नीतियों का समर्थन करते हैं, जो बड़ी कंपनियों को वीजा प्रणाली का गलत फायदा उठाने और नियोक्ताओं को आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करने से रोकें। हालांकि, उन्होंने स्टिट के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए पूछा कि दोनों दलों की सहमति से सुधार की वकालत करके वह वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। वेंस ने लिखा, बहुत से लोगों को यह उन लोगों को माफी देने की कोशिश जैसा लगता है, जिन्होंने हमारे कानूनों को तोड़ा है। यह नैतिक रूप से और चुनावी नजरिए से भी विनाशकारी होगा।

स्टिट ने ट्रंप को दी द्विदलीय पहल की सलाह : स्टिट ने यूटा में नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के न्यू गवर्नर्स लीडरशिप फोरम के दौरान पोलिटिको से बातचीत में अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ट्रंप को अपने प्रशासन के आखिरी दो वर्षों का उपयोग आव्रजन प्रणाली में बड़े बदलावों के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को एक साथ लाने में करना चाहिए। स्टिट ने कहा, यह इतना भी जटिल नहीं है। लेकिन समस्या वाशिंगटन, डीसी में है, जहां हर पक्ष को लगता है कि वे इस मुद्दे पर जीत रहे हैं। उन्होंने मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के कमजोर प्रदर्शन की आशंका के लिए भी इसी मुद्दे से जुड़े राजनीतिक ध्रुवीकरण को जिम्मेदार ठहराया। ओक्लाहोमा के गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका को सुरक्षित सीमाओं, देश में आने वाले लोगों की स्पष्ट ट्रैकिंग और गहन पृष्ठभूमि जांच की जरूरत है। साथ ही, उन्होंने राज्य के नेताओं को श्रम की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक अधिकार देने की वकालत की। इसमें गवर्नरों को यह अधिकार देना भी शामिल है कि जब कोई व्यवसाय किसी कर्मचारी को प्रायोजित करे, तो वे उसे वर्क परमिट जारी कर सकें।

इंडोनेशिया की कैंडी फैक्टरी में भीषण आग, तीन की मौत; 36 कर्मचारी लापता, अपनों की तलाश में भटक रहे परिजन

जकार्ता, एजेंसी। इंडोनेशिया के बैंटन प्रांत में शनिवार को एक कैंडी फैक्टरी में भीषण आग लग गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं, 36 कर्मचारी गायब हैं। बचाव दल उनकी तलाश में जुटे हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आग बैंटन प्रांत के सेरांग जिले में स्थित पीटी फोनुसा अगुंग मुलिया फैक्टरी में लगी। यह इलाका राजधानी जकार्ता के पास है। यह फैक्टरी मिल्किटा नाम के ब्रांड की कैंडी और स्नैक्स बनाती है। ये उत्पाद दूध से तैयार किए जाते हैं।

कितने लोगों को बचाया गया: राष्ट्रीय खोज और बचाव एजेंसी ने एक बयान जारी किया। इसके मुताबिक, फैक्टरी से 15 लोगों को जिंदा बचाया गया है। इनमें चार



घायल कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं, बचाव दल अब भी लापता 36 कर्मचारियों की तलाश कर रहे हैं।

बैंटन खोज और बचाव एजेंसी के संचालन अधिकारी रिज्की द्वियांतो ने बताया कि फैक्टरी के कई हिस्सों में अब भी आग लगी हुई है। उन्होंने कहा, कई जगहों पर आग अब भी जल रही है। दमकलकर्मी आग बुझाने के साथ ही प्रभावित जगहों को ठंडा करने में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि आग लगने के 12 घंटे से ज्यादा समय बाद भी दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में जुटे थे। सेरांग जिले और बैंटन प्रांत की दमकल टीमें फैक्टरी के अलग-अलग हिस्सों में आग बुझा रही थीं।

आग के बाद फैक्टरी में कैसा था मंजर : टेलीविजन पर दिखाई गई तस्वीरों में तीन मंजिला फैक्टरी आग की लपटों से घिरी नजर आई। आसमान में काले धुएं का गुबार उठ रहा था। इससे आसपास रहने वाले लोगों और कर्मचारियों में दहशत फैल गई। आग से जली इमारत के फर्श पर मुड़ी हुई धातु के टुकड़े बिखरे पड़े थे। छत की लोहे की चादरें भी जलकर काली हो गई थीं। वहां अन्य मलबा भी फैला हुआ था।

लापता कर्मचारियों के परिजन कर रहे इंतजार : फैक्टरी के बाहर लापता कर्मचारियों के परिजन बेचैन होकर इंतजार कर रहे थे। वे अपने परिवार के उन सदस्यों की खबर मिलने की उम्मीद कर रहे थे, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। आग लगने की सही वजह का अभी पता नहीं चला है। अधिकारियों ने यह भी नहीं बताया कि आग लगने के समय सभी लापता कर्मचारी फैक्टरी के अंदर ही थे या नहीं। हालांकि, आग से बचकर निकले लोगों ने बताया कि तीसरी मंजिल पर लगी एक ठंडा करने वाली मशीन से आग शुरू हुई थी।

यमन में सऊदी ने किए हवाई हमले, होदेदा शहर को बनाया निशाना; हूती विद्रोहियों ने क्या दावा किया

सना/रियाद, एजेंसी। सऊदी अरब ने लाल सागर के तट पर बसे यमन के बंदरगाह शहर होदेदा पर शनिवार शाम हवाई हमले किए। सऊदी लड़ाकू विमानों ने कई हमले किए। हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले अल-मसीरा टीवी ने इसकी जानकारी दी। चैनल ने इन हमलों को सऊदी आक्रामकता बताया। हालांकि, उसने हमलों में मारे गए या घायल हुए लोगों की संख्या नहीं बताई। नुकसान की जानकारी भी नहीं दी। एक स्थानीय निवासी ने समाचार एजेंसी शिन्हुआ को बताया कि शहर में पांच से ज्यादा जोरदार धमाके हुए। उस समय भी लड़ाकू विमान आसमान में उड़ रहे थे। निवासी ने कहा, धमाके बेहद तेज थे। हम अब भी अपने ऊपर विमानों की आवाज सुन सकते थे।

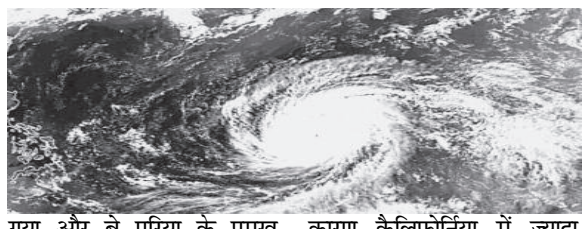
हूती विद्रोहियों ने क्या दावा किया : वहीं, हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरीया ने अलग से बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में सऊदी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने यमन के आठ प्रांतों में 71 हमले किए। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, इन हमलों में लोग हताहत हुए हैं। सरीया ने एक्स पर एक बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि ताजा हमलों के बाद सऊदी अरब की ओर से किए गए हवाई और मिसाइल हमलों की संख्या 5,500 हो गई है। यह संख्या सैन्य तनाव दोबारा बढ़ने के बाद से अब तक हुए हमलों की है।

सऊदी ने हूती विद्रोहियों के कितने ड्रोन और मिसाइल रोके : इस बीच, सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मलिकी ने शनिवार को एक्स पर बताया कि गठबंधन की सेना ने हूतियों की ओर से रियाद की तरफ भेजे गए एक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इससे पहले, गठबंधन ने बताया था कि उसकी सेना ने रियाद की ओर दागी गई हूती विद्रोहियों की तीन बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। गठबंधन ने एक और ड्रोन को रोकने की जानकारी दी। यह ड्रोन हूतियों ने सऊदी अरब के दक्षिणी क्षेत्र की ओर भेजा था। ये घटनाएं ऐसे समय हुई हैं, जब यमन में हूती विद्रोहियों और सरकारी सेना के बीच लड़ाई तेज हो रही है। यमन की सरकारी सेना को सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन हासिल है। पिछले कुछ दिनों में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों और तेल ठिकानों पर कई बार मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया है। वहीं, हूती विद्रोहियों के मीडिया संस्थानों ने यमन में सऊदी अरब के हवाई हमले तेज होने की खबरें दी हैं। यमन में दिसंबर 2014 के आखिर से संघर्ष जारी है। उस समय हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना और उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सैन्य कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन की सरकार के समर्थन में की गई थी।

कैलिफोर्निया में बाढ़ और समुद्री लहरों का खतरा, अल नीनो और ऊंचे ज्वार से तटीय इलाकों पर संकट

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड दर की बारिश, समुद्र की ऊंची उठती लहरों और कमजोर समुद्री तटबंधों ने खतरे की आशंका बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अल नीनो इफेक्ट और असामान्य रूप से ऊंचे समुद्री ज्वार के कारण इस सप्ताह राज्य के तटीय इलाकों में बाढ़, कटाव और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने का खतरा है।

तूफानी सिस्टम से फ्लैश फ्लड का खतरा : अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा ने गुरुवार तड़के कैलिफोर्निया के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को नए तूफानों को लेकर सतर्क किया। उन्होंने कहा, बारिश लाने वाला तूफानी सिस्टम बेहद सक्रिय है और एक घंटे में एक इंच (करीब 25.4 मिलीमीटर) से अधिक बारिश दर्ज की गई है। इसी वजह से कई जगहों पर फ्लैश फ्लड आने की चेतावनी जारी की गई है। सैन फ्रांसिस्को में बारिश ने तोड़ा 100 साल पुराना रिकॉर्ड समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, सुपर अल नीनो के प्रभाव से वायुमंडलीय नमी के एक शक्तिशाली प्रवाह के कारण बुधवार को सैन फ्रांसिस्को में बाढ़ जैसे हालात बन गए। शहर में एक ही दिन में 2.64 इंच बारिश दर्ज की गई, जिसने इस तारीख के लिए सौ साल से भी पुराने बारिश के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बारिश के कारण कई इमारतों में पानी भर



गया और बे एरिया के प्रमुख राजमार्गों पर वाहन पानी में फंस गए। बुधवार दोपहर तक 51 हजार से अधिक बिजली उपभोक्ताओं की आपूर्ति भी बाधित हो गई।

अल नीनो से बढ़ सकती है बारिश और समुद्री जलस्तर : अल नीनो एक ऐसा मौसमी पैटर्न है जिसमें उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इसके कारण कैलिफोर्निया में ज्यादा बारिश और तूफान आ सकते हैं। यह यूएस के पश्चिमी तट पर समुद्र के जलस्तर को कुछ समय के लिए बढ़ा सकता है, जिससे ऊंची लहरें और ज्वार-भाटा सामान्य से कहीं ज्यादा अंदर तक पहुंच सकते हैं।

दक्षिणी कैलिफोर्निया में ऊंची लहरों से तटीय कटाव : गुरुवार को दक्षिणी कैलिफोर्निया के तटों पर बड़ी-बड़ी लहरें टकराती रहीं, जिससे पहले आए तूफानों से हुआ कटाव और नुकसान और भी बढ़ गया। अक्टूबर में, क्रिस्टल कोव स्टेट पार्क के पास पैसिफिक कोस्ट हाईवे के नीचे एक तटीय ढलान में 360 फुट लंबी दरार आ गई थी। इसके चलते कैल्ट्रान्स को दोनों दिशाओं में ट्रैफिक को एक-एक लेन तक सीमित करना पड़ा था, ताकि कर्मचारी ढलान को स्थिर करने का काम कर सकें।

मालिबू और लॉस एंजिलिस में 9 फुट तक ऊंची लहरों की चेतावनी : मालिबू और लॉस एंजिल्स काउंटी के समुद्र तटों के लिए शुक्रवार सुबह 9 बजे तक हाई सर्फ एडवाइजरी (ऊंची लहरों की चेतावनी) जारी है, जिसमें 6 से 9 फुट ऊंची लहरें उठने की आशंका है।

अगले सप्ताह किंग टाइड्स से बढ़ेगा खतरा : वैज्ञानिकों का मानना है कि असली चुनौती अगले हफ्ते आएगी, जब रविवार से 27 नवंबर के बीच असामान्य रूप से ऊंचे किंग टाइड्स (बहुत ऊंचे ज्वार) आएंगे। इस दौरान बड़ी लहरें उठ सकती हैं और और भी बारिश हो सकती है। सोमवार से, दक्षिणी कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में तटीय जलस्तर 8 फुट से भी ऊपर जा सकता है। कैलिफोर्निया कोस्टल कमीशन के अनुसार, इस मौसम के सबसे ऊंचे ज्वार 24-26 नवंबर, 23-25 दिसंबर और 21-22 जनवरी को आएंगे।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक: सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बाल-बाल बचे सांसद पप्पू यादव, गड्ढे में गिरी कार



पटना, एजेंसी। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव के काफिले की एक कार कटिहार में सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में सांसद पप्पू यादव बाल-बाल बच गए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पप्पू यादव कटिहार के सालमारी में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जानकारी के अनुसार, कटिहार के कदवा थाना अंतर्गत कुम्हरी पेट्रोल पंप के पास उनके काफिले के साथ सुरक्षा में चल रही पुलिस की गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई। इस घटना में काफिले में मौजूद एक पुलिस कर्मी को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद सांसद पप्पू यादव ने कुम्हरी से ही पूर्णिया के लिए वापस लौटना उचित समझा और अपना निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कदवा थाना की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और सड़क से नीचे उतरी दुर्घटनाग्रस्त पुलिस वाहन को बाहर निकालने की कार्रवाई की।

सीएम विजय की अपने सहयोगी दलों के विधायकों के साथ अहम बैठक

चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय सोमवार को सहयोगी दलों के विधायकों से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएम विजय ग्रीनवेज रोड स्थित अपने आधिकारिक आवास पर भेंट करेंगे, जहां उनका कार्यालय भी है और वे अक्सर अहम बैठकें करते हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री गठबंधन में शामिल विधायकों के साथ परामर्श करेंगे। यह बैठक दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें राज्य सरकार का समर्थन करने वाले गैर-टीवीके विधायक शामिल हो सकते हैं। इनमें कांग्रेस, वीसीके, एमडीएमके, आईयूएमएल और वाम दलों के विधायक शामिल हैं। बता दें इससे पहले 1 जुलाई और 9 सितंबर को सीएम विजय की तरफ से बुलाई गई परामर्श बैठकों में वाम दलों सीपीआई और सीपीआई(एम) ने हिस्सा नहीं लिया था।

नोएडा सेक्टर-6 में प्लास्टिक सामान बनाने की कंपनी में भीषण आग

- आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया, कोई जनहानि नहीं

नोएडा, एजेंसी। नोएडा के सेक्टर-6 स्थित एक कंपनी में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग इसकी चपेट में आ गई। कंपनी में प्लास्टिक से सजावटी सामान बनाने का काम होता है। प्लास्टिक से बने उत्पाद और अन्य सामग्री मौजूद होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। जानकारी के मुताबिक सेक्टर-6 में स्थित निजी कंपनी में देर रात आग लग गई। शुरुआत में कंपनी के अंदर से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दीं। कुछ ही देर में आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल विभाग को तत्काल सूचना दी गई। पूरी बिल्डिंग में आग फैलने के कारण दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल कर्मियों ने कई घंटों तक अभियान चलाकर आग पर काबू पाया। इस दौरान बिल्डिंग के अंदर मौजूद गर्म हिस्सों और आग से प्रभावित स्थानों पर पानी डालकर उन्हें ठंडा किया गया ताकि अंदर सुलग रही आग दोबारा न भड़क सके। इस घटना में राहत की बात यह रही कि अब तक किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि आग की चपेट में आने से कंपनी की बिल्डिंग और उसमें रखे सामान को कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन किया जाना बाकी है। देर रात हुई इस घटना के बाद आसपास के इलाके में काफी देर तक अफरा-तफरी मची रही। फिलहाल दमकल विभाग की टीम मौके पर कूलिंग की कार्रवाई में जुटी हैं।

मोदी और शाह की जोड़ी कोई साजिश रच रही या फिर झूठ के जाल में फंस गए

-संसद सत्र और परिसीमन को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया दावा



नई दिल्ली , एजेंसी। संसद सत्र और परिसीमन को लेकर बने सस्पेंस के बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी या तो कोई खतरनाक साजिश रच रही है, या फिर वे अपने ही बुने झूठ और दिखावे के जाल में फंस गए हैं।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को एक्स पर लिखा- पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी क्या खेल खेल रही है, अगर मान लें कि यह जोड़ी अभी भी साथ है? उन्होंने कहा कि यदि मान लें कि शीतकालीन सत्र होने वाला है तो अब तक देश को पता चल जाना चाहिए था कि संसद का शीतकालीन सत्र कब होगा। यदि मान लें कि इसे फिर से बुलाया जाने वाला है, तो अब तक देश को पता चल जाना चाहिए था कि मानसून सत्र को कब फिर से बुलाया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकसभा में किसी तरह दो-तिहाई बहुमत जुटाने की इस जोड़ी की हताश कोशिशों को देखते हुए, देश को यह जानने का हक है कि परिसीमन को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह का फॉर्मूला क्या है। जयराम रमेश ने कहा क्थ् यह लगातार बना हुआ सस्पेंस साफ तौर पर दो बातें बताता है- पहला यह जोड़ी खुद उलझन में है और अपने ही बुने झूठ और दिखावे के जाल में फंस गई है, या दूसरा- कोई बहुत खतरनाक साजिश रची जा रही है।
उन्होंने आगे कहा कि जो भी हो जीटीए यानी ज्ञानेश-थेफ्ट-अरेंजर्स की यह जोड़ी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। दुख की बात है कि संसद जैसी संस्था, जो पहले से ही काफी कमजोर हो चुकी है, इस खतरनाक जोड़ी की हरकतों की वजह से और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही है। इससे पहले, साल 2025 में 5 नवंबर को तत्कालीन संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर को समाप्त होगा। हालांकि, मौजूदा स्थिति में सत्र को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

सूखे से निपटने को तैयार महाराष्ट्रः सुनेत्रा पवार ने बताए उपाय



मुंबई , एजेंसी। महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने घोषणा की कि राज्य सरकार सूखे की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि प्रभावित 310 तालुकाओं में पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने, प्रभावी जल प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के मौके पैदा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पुणे के बालेवाडी स्थित शिव छत्रपति खेल परिसर के दौरे के दौरान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि महायुति सरकार ने किसानों की मदद के लिए जल प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था की है।
उन्होंने बताया कि किसानों को बड़े पैमाने पर चारे की फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें आवश्यक बीज भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नहरों और बांधों के आसपास रहने वाले किसानों से भी चारे की खेती करने का आग्रह किया गया है। महायुति सरकार इन किसानों से चारा खरीदेगी, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय होगी। रोजगार सृजन के संबंध में, डिप्टी सीएम पवार ने बताया कि महायुति सरकार ने रोजगार गारंटी योजना के तहत गर्मियों में विभिन्न कार्य कराने का प्रस्ताव रखा है, ताकि अधिक लोगों को काम मिल सके और उनकी आजीविका चलाने में मदद हो सके।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कुल 358 तालुकाओं में से 310 को सूखाग्रस्त घोषित किया है। केंद्र से सहायता, विशेष रूप से किसानों को पांच-पांच हजार रुपये की अग्रिम राहत के संबंध में अपेक्षित समयसीमा के सवाल पर, उपमुख्यमंत्री ने कोई निश्चित जानकारी नहीं दी। हालांकि, उन्होंने दृढ़ता से कहा कि राज्य सरकार अपनी ओर से सूखे की इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सज्ज है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

बीजेपी ने यूपी मिशन-2027 के लिए 403 विधानसभा सीटों पर चुनावी घेराबंदी की शुरू

- अगले महीने यूपी का दौर कर सकते हैं शाह, सियासी समीकरण साधने पर रहेगा जोर

लखनऊ, एजेंसी। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अगले महीने से अमित शाह का उत्तर प्रदेश दौरा संभावित है। इस दौरान उनका फोकस संगठन को मजबूत करने, कमजोर सीटों पर पार्टी की स्थिति सुधारने और प्रदेश के सियासी समीकरण साधने पर रहेगा। माना जा रहा है कि शाह अपने दौरे के जरिए यूपी में बीजेपी के चुनावी अभियान की कमान संभालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे में इन सभी तैयारियों की समीक्षा के साथ चुनावी रोडमैप को अंतिम रूप देने पर जोर रह सकता है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी कमजोर सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और बूथ स्तर तक संगठन को धार देने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी आने वाले दिनों में संगठन से लेकर जनसंपर्क तक अभियान और तेज कर सकती है। इसके साथ ही बीजेपी ने मिशन-2027 के लिए प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनावी घेराबंदी शुरू कर दी है। इसके तहत पार्टी ने 40 पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी है। हर दो जिलों के बीच एक पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। ये पर्यवेक्षक गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएंगे और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे। इसके साथ ही जनता के बीच सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक भी जुटाएंगे। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर पार्टी चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी देगी। वहीं संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने छह क्षेत्रों में दूसरे राज्यों से आए संगठन मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी का जोर उन इलाकों और सीटों पर विशेष रूप से है, जहां संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है। बीजेपी की रणनीति के तहत संगठन, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचने की तैयारी है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके।

आरक्षण बिल पर सियासी हलचलः विपक्ष ने लगाया सांसद खरीद का आरोप



नई दिल्ली , एजेंसी । संसद के बहुप्रतीक्षित शीतकालीन सत्र की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। इसी बीच, परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक और महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की सियासत गरमा गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, दावा किया जा रहा है कि सरकार के पास इन महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए आवश्यक 40-50 सांसदों की संख्या कम पड़ रही है, जिसके चलते पार्टियों को तोड़ने और सांसदों की खरीद-फरोख्त की तैयारी की जा रही है।
शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया है कि इस संख्या को जुटा पाने में असमर्थता के चलते सत्ताधारी दल शीतकालीन सत्र को दांव पर लगा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि सांसदों की खरीद के लिए प्रति सांसद 150 करोड़ रुपये की रकम तय की गई है। राउत के अनुसार, इस काम के लिए महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री को भी लगाया गया है, हालांकि उन्होंने इस दौरान किसी नेता का नाम नहीं लिया।
राउत ने अपने दावे में कहा, सरकार जिद और अहंकार पर उतर आई है। शीतकालीन सत्र इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वे चाहते हैं कि परिसीमन बिल हम मंजूर कर लेंगे। यह उनका ईगो है और इस ईगो के लिए एक शीतकालीन सत्र खाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, देश, संविधान और संसद की चिंता नहीं की जा रही है, बल्कि यह तय किया गया है कि किसी भी हालत में परिसीमन बिल मंजूर किया जाएगा। इसके लिए जो 40-45 सांसदों का आंकड़ा कम पड़ रहा है, उसे छोटी-छोटी पार्टियों को खरीदकर या दबाव में लाकर पूरा किया जाएगा। अगर पार्टियां नहीं टूट रहीं, तो कुछ सांसदों को खरीद लेंगे।
राज्यसभा सांसद राउत ने सांसदों को खरीदने के लिए 150 करोड़ रुपये की पेशकश का दावा करते हुए कहा, यह भाजपा के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भाव है एक सांसद का 150 करोड़। पार्टी का व्हिप तोड़कर वोट करो, आपको अयोग्य नहीं किया जाएगा। न ओम बिरला जी करेंगे, न चुनाव आयोग करेगा। आराम से पार्टी व्हिप तोड़कर वोट करो और 150 करोड़ रुपये लेकर जाओ। उन्होंने यह भी दावा किया कि पूरा पैसा महाराष्ट्र से जाएगा और एक बड़े मंत्री ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हालांकि, इन आरोपों को सत्ता पक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने राउत के दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए सवाल किया, 150 करोड़ रुपये दे रहे हैं, आपसे किसने बताया? उसको सामने लाओ और कहो न। दरअसल, सरकार परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की तैयारी में है, जिसका उद्देश्य लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करना और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करना है। इस विधेयक को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत यानी 361 वोटों की जरूरत होगी। 540 सदस्यों वाले मौजूदा सदन में, सत्ताधारी दल के पास 320 सदस्य हैं। ऐसे में, आवश्यक संख्या जुटाने के लिए उन्हें विपक्षी दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी।

ऋषिकेश में विदेशी महिलाओं ने उठाया गंगा सफाई का बीड़ा, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे तारीफ

देहरादून ,एजेंसी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में कुछ विदेशी महिलाएं हाथों में दस्ताने पहने और काले कचरे के थैले लिए गंगा घाट पर फैला प्लास्टिक और अन्य कचरा साफ करती दिख रही हैं। चट्टानों के बीच दबी पन्नियां हों या रेत में पड़ा कूड़ा, ये महिलाएं बिना किसी दिखावे के, पूरी लगन से एक-एक चीज को उठाकर थैले में डाल रही हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर द्वारा साझा किए गए वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स ने भी अपनी हैरानी जताकर कहा कि जहां लोग अपनी पवित्र नदी में कचरा फेंकने से बाज नहीं आते, वहीं दूसरे देशों से आई ये महिलाएं हमारी विरासत को बचाने की कोशिश कर रही हैं।

जब पाकिस्तान अपने आतंकी ढांचे को खत्म करेगा तभी होगी द्विपक्षीय बातचीत

-पाक मंत्री मलिक के भारत दौरे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान आया सामने

नई दिल्ली , एजेंसी। पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मसूद मलिक के भारत दौरे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों के बावजूद मल्टीलेटरल फोरम की अपनी जगह है। उन्होंने दोहराया कि दोनों देशों के बीच बातचीत तभी शुरू हो सकती है, जब पाकिस्तान अपने आतंकी ढांचे को खत्म कर दे। थरूर ने स्पष्ट किया कि जब तक पाकिस्तान अपने इलाके से चल रहे आतंकवादी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक भारत पहले की तरह द्विपक्षीय बातचीत फिर से शुरू नहीं करेगा।
उन्होंने कहा कि भले ही उन दिनों भी पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते काफी खराब थे, तो ये ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको समझना होगा। मल्टीलेटरल फोरम की अपनी जगह है। थरूर ने आगे कहा कि जहां तक द्विपक्षीय रिश्तों की बात है, हमने यह साफ कर दिया है कि पहले जिस तरह की बाइलेटरल बातचीत होती थी, वह तभी फिर से शुरू हो सकती है जब पाकिस्तान अपने देश में आतंक के इंफास्ट्रक्चर को खत्म कर दे। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की स्थिति दोहराते हुए कहा कि आप ये टेररिस्ट कैंप, हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग ग्राउंड वगैरह नहीं रख सकते जिनका इस्तेमाल रेगुलर तौर पर हमारे लोगों पर हिंसा करने के लिए किया जा रहा है और फिर बातचीत की उम्मीद करें। उन्होंने कहा कि कोई भी अपने सिर पर बंदूक तानकर बात नहीं करना चाहता और हम भी ऐसा नहीं करने वाले हैं।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के कार्यक्रम में शामिल होने आए पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक ने आतंकवाद के मुद्दे पर कहा कि इस विषय पर किसी भी तरह की चर्चा ठोस सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा क्षेत्र आतंकवाद की चपेट में है, इसलिए इसका समाधान भी सामूहिक रूप से मिलकर निकाला जाना चाहिए। मलिक ने यह भी वकालत की कि एक ऐसा फोरम बनाया जाना चाहिए, जहां इन सबूतों को सामने लाया जा सके और उसी आधार पर हर



मुद्दे का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि पूरा क्षेत्र इस समस्या से जूझ रहा है और अगर आतंकवाद से निपटने में किसी का सबसे बड़ा हित है तो वह किसी और से ज्यादा पाकिस्तान का है।

गोवा में सीजेपी ने फूंका चुनावी बिगुल कहा- धारा 39ए हटाना होगी

सत्रावसान नहीं होने को लेकर चिंतित विपक्ष, लग रही साजिश



पणजी , एजेंसी। गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी अब गोवा में ही रहकर एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगी और सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। दीपके ने बताया कि सीजेपी गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र भी जारी करेगी, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। दीपके ने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता गोवा नगर एवं ग्रामीण नियोजन अधिनियम की धारा 39ए को निरस्त करवाना है। यह धारा स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना कर रही है, जिससे यह भाजपा सरकार के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बन गई है।
सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने गोवा में अपनी पार्टी के दीर्घकालिक रहने का संकल्प दोहराते हुए कहा, हमें भारत बचाना है और भारत का निर्माण करना है। इस देश का भविष्य कोई 75 साल का महामानव नहीं, बल्कि यहां के युवा हैं। दरअसल, धारा 39ए को गोवा नगर एवं ग्रामीण नियोजन अधिनियम 1974 में 2024 में हुए एक संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। यह प्रावधान बोर्ड की मंजूरी के बाद किसी भी भूखंड का ज़ोन बदलने की अनुमति देता है, जिसके लिए जनता से केवल 30 दिनों के भीतर आपत्तियां मांगी जाती हैं। स्थानीय निवासी इस धारा का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, उनका तर्क है कि यह पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाएगी और उद्योगपतियों व प्रभावशाली लोगों के हितों को बढ़ावा देगी। इससे कृषि योग्य और वन भूमि का उपयोग भी निर्माण या शहरी विकास के लिए किया जा सकेगा, जो गोवा की पारिस्थितिकी और संस्कृति के लिए खतरा है।
आशुतोष रांका ने बताया कि एक आंदोलन ने लोगों को एक मंच पर इकट्ठा किया था। उन्होंने सीजेपी की दीर्घकालिक रणनीति पर जोर देते हुए कहा, सीजेपी अब गोवा में लंबे समय के लिए आई है। अब यहां लंबा खेल चलेगा। कॉकरोच कभी नहीं मरेंगे। दीपके ने कहा कि सीजेपी अब गोवा की पहचान और जमीन के लिए लड़ाई लड़ेगी और उनके घोषणापत्र में धारा 39ए के खिलाफ संघर्ष को प्रमुखता दी जाएगी। उनका आरोप है कि गोवा की अनूठी संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।

अनंत सिंह की बेटी की शादी- किन्नरों ने मांगा सवा करोड़ का नेग

पटना , एजेंसी । मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी इन दिनों बिहार से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा में है। हाल ही में दानापुर स्थित ऑर्गेनिक रिजॉर्ट में हुए भव्य तिलक समारोह के दौरान एक खास नजारा देखने को मिला, जब किन्नरों की टोली ने अनंत सिंह के होने वाले समधी से सवा करोड़ रुपये का नेग मांगकर सभी को चौंका दिया। अपने पारंपरिक अंदाज में नाच-गाना करते हुए किन्नरों ने ठिठोली कर कहा कि छोटे सरकार के यहां शादी हो रही है, तब नेग भी दिल खोलकर मिलना चाहिए। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि इस बार सवा करोड़ रुपये दे दीजिए, इसके बाद वे सीधे तब आएंगे, जब घर में पोता होगा। इस बातचीत का वीडियो भी खूब चर्चा बटोर रहा है, जहां किन्नरों ने परिवार को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद भी दिया।

1977 के चुनाव को प्रभावित करने कांग्रेस ने कारोबारियों से लिए थे 113 करोड़

बीजेपी सांसद ने अवैध सांठगांठ और काले धन के इस्तेमाल का लगाया आरोप

रांची, एजेंसी । बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर पिछले कई दशकों से कारोबारियों से अवैध सांठगांठ और काले धन के इस्तेमाल से चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोमवार को एक्स पर 70 के दशक में प्रकाशित एक खबर की पुरानी कटिंग साझा की। इसके आधार पर दावा किया कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने 1977 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए कारोबारियों से 113 करोड़ रुपए लिए थे। दुबे के मुताबिक उस समय खर्च की गई यह रकम आज के मूल्य के हिसाब से करीब 25 हजार करोड़ रुपए बैठती है। दुबे ने पुरानी खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव में लोकसभा के प्रत्येक उम्मीदवार को दो लाख रुपए और दो जीप उपलब्ध कराई गई थीं। उन्होंने कांग्रेस पर चुनावी चंदे और कारोबारी हितों के बीच पुराने गठजोड़ का आरोप लगाया और इसे देश की राजनीति का काला इतिहास बताया। दुबे सोशल मीडिया पर 'कांग्रेस का काला अध्याय' नाम से शृंखलाबद्ध अभियान चला रहे हैं। इसकी 252वीं कड़ी में उन्होंने लिखा कि 23 नवंबर 1978 को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की रिपोर्ट मीडिया में प्रकाशित हुई थी। उनके मुताबिक इस रिपोर्ट में इंदिरा गांधी और कारोबारियों के बीच कथित सांठगांठ का खुलासा किया था।



दुबे ने सबसे ज्यादा चंदा देने का आरोप आरपी गोयनका पर लगाया। उन्होंने दावा किया कि गोयनका को तीन अक्टूबर 1977 को काले धन के मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने कई बार छापेमारी भी की थी। बीजेपी सांसद ने सरकारिया आयोग और हजारी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि बिड़ला समूह ने 1957 से 1977 के बीच कांग्रेस को धन देकर लाइसेंस हासिल किए। उन्होंने कोका-कोला और आईबीएम जैसी विदेशी कंपनियों पर भी कांग्रेस को धन देने का आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि इन आरोपों से घिरी इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी को तोड़ने के लिए हर तरीका अपनाया।